जागृति

वर्ष:62
अंक: 5
मुम्बई
अप्रैल 2018

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और आयोग के सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माननीय प्रधान मंत्री के विज़न और प्रेरणा ने खादी, पीएमईजीपी और हनी मिशन में केवीआईसी की प्रगति को नयी ऊँचाईयां प्रदान की हैं।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केवीआईसी के सौर चरखा कारीगरों को पारिश्रमिक चेक प्रदान करते हुए।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष 62 अंक-5 मुंबई अप्रैल 2018

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
के. एस. राव

उप संपादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे

कलाकार
दिलीप पालकर
सी.एच.पुनवटकर

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400056
के लिए प्रकाशित
ईमेल: jagritikvic@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हो.

इस अंक में....

समाचार सार .....3 से 30

एम.एस.एम ई. मंत्री द्वारा भरूच, गुजरात में नीम इकाई का उद्घाटन....
राष्ट्रपति भवन ने आयोग द्वारा स्थापित मधुमक्खी वाटिका.....
एमएसएमई मंत्री द्वारा केआरडीपी योजना के तहत सामान्य.....
शंभुराजे कारोबारी समूह के साथ एम.ओ.यू.....
आयोग के पश्चिम क्षेत्र को उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान.....
हस्तकला के साथ एम.ओ.यू.....
आयोग में महिला दिवस मनाया गया.....
आयोग में महिला दिवस आयोजित .....
अब खादी के कत्तिनों को मिलेगी दोगुनी मजदूरी.....
देहरादून में चरखा वितरण कार्यक्रम.....
रैम्प पर खादी.....
खादी सूत की माला: चरखा संग्रहालय के लिए एक अनूठा टिकट.....
ऐसे 'कारीगर'-जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है आयोग के 'आपरेशन.....
आयोग द्वारा पी.एम.ई.जी.पी. पर जागरूकता शिविर.....
कुपवाड़ा में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम.....
खादी पंचायत के तहत खादी सम्मेलन.....
केरल में 'इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील' का वितरण.....
सदस्य(दक्षिण क्षेत्र) द्वारा उर्वू स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी.....
एर्नाकुलम में खादी इंडिया प्रदर्शनी 2018.....
स्टील और काष्ठ फर्नीचर के कारीगरों हेतु डिजाइन.....
ट्रांसजेंडरों के लिए पी.एम.ई.जी.पी. के तहत विशेष जागरूकता.....
केवीआईसी के 'स्वच्छता अभियान' से सरकार के 153 करोड़.....
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दक्षिण क्षेत्र) द्वारा आयोग के.....
जेल के कैदियों के लिए रेशा उत्पाद बनाने हेतु प्रशिक्षण.....
हिंदी कार्यशालाएं.....

प्रत्युत्तर .....31 से 32

* 'द इकोनॉमिक टाइम्स' में प्रकाशित एक लेख में पूछा गया: व्हाट्स द डील विद खादी?

प्रेस कवरेज .....33 से 42

एमएसएमई मंत्री द्वारा भरूच, गुजरात में नीम इकाई का उद्घाटन

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन लिमिटेड (जीएनएफसी) द्वारा स्थापित नीम साबुन इकाई का उद्घाटन-केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने किया और श्री सिंह उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

यह नवाचार परिवर्तन नीम परियोजना के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं जिसने पिछले तीन वर्षों में 45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय सृजन करके 4.5 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने में योगदान दिया है।

जीएनएफसी की सीएसआर शाखा नर्मदानगर ग्रामीण विकास सोसायटी (एन.ए.आर.डी.ई.एस) ने पीएमईजीपी योजना के अनुसार इकाई के लिए आधारभूत संरचना और महिलाओं के बीच सक्षम कौशल विकास को सक्रिय रूप से विकसित किया। नीम साबुन इकाई के लिए एन.ए.आर.डी.ई.एस. ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ समन्वय किया है, जिससे इकाई की 4.3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मूल्य के 225 मीट्रिक टन नीम साबुन का निर्माण करने की क्षमता हुई है। इससे महिलाओं को भी संगठित किया गया है और भरूच में आईटीआई के साथ नीम साबुन बनाने के कार्य में उन्हें प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें साबुन बनाने के कुशल कारीगर के रूप में प्रमाणित किया गया है।

उद्घाटन समारोह में बोलते हुए श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि "मैं माननीय प्रधान मंत्री के विजन -100% यूरिया के नीम कोटिंग को कार्यान्वित करने के लिए जीएनएफसी के प्रबंध निदेशक डॉ. गुप्ता को बधाई देता हूं"। यह साबुन केवल एक कार्बनिक नीम साबुन नहीं है, बल्कि यह भारतीय ग्रामीण महिलाओं के प्रयास और कड़ी मेहनत से बनाया जाता है। हम जीएनएफसी द्वारा बनाए गए प्रत्येक नीम साबुन पर उन महिलाओं के चेहरे की कल्पना करते हैं, जिन महिलाओं ने नीम साबुन बनाने में कड़ी मेहनत की है। जब नीम के बीज इन उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो महिलाओं को 10 गुना अधिक आर्थिक लाभ मिलता है और जिससे उनकी बेहतर आजीविका होती है।"

गुजरात सरकार के कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालन और परिवहन मंत्री श्री आर.सी. फाल्डू ने न केवल गुजरात में बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आजीविका प्रदान करने के लिए जीएनएफसी के प्रयासों को बधाई दी। इस अवसर पर सम्मानित अन्य गणमान्य महानुभावों में भरूच के सांसद श्री मनसुखभाई वासव; भरूच के विधायक श्री दुष्यंतभाई पटेल और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक, अहमदाबाद श्री संजय हडाऊ उपस्थित थे।

श्री गिरिराज सिंह ने नीम कॉम्प्लेक्स और विनिर्माण सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए जीएनएफसी द्वारा अपनाए गए संपोषणीय व्यापार मॉडल की सराहना की और इकाई की स्थापना के 3 महीनों में ही उल्लेखनीय वृद्धि को भी सराहया। इकाई को आंशिक रूप से पीएमईजीपी के तहत **24** लाख रुपये के अनुदान के साथ वित्तपोषित किया गया है।

(शेष.. पृष्ठ 29 पर)

राष्ट्रपति भवन ने आयोग द्वारा स्थापित मधुमक्खी वाटिका से पहली बार शहद का स्वाद लिया

नई दिल्ली: दुनिया में सबसे बड़े राष्ट्रपति भवन की मधुवाटिका में - अब शहद की पैदावार शुरू हो गई है ! मंगलवार को, राष्ट्रपति भवन के उद्यान वाटिका में एक नए युग की शुरूआत हुई है, जहाँ प्रचुर मात्रा में वनस्पतियां और जीवों का समावेश है- जिनमें आम, भारतीय ब्लैकबेरी (जामुन), नीम और ड्रमस्टिक (सहजन की फली) इत्यादि शामिल हैं, इस वाटिका से 186 किलोग्राम से अधिक शहद निकाला गया। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी उपस्थित थे।

इससे पूर्व, सभी गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति में मधुमक्खियों के बक्से खोले गए और उनके सामने स्टेनलेस स्टील के डिब्बों में शहद निकाला गया। तत्पश्चात, शहद को राष्ट्रपति भवन के नाम को प्रदर्शित करने वाले बॉटल्स में पैक किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने नींबू पानी में शहद डालकर नैसर्गिक शहद का स्वाद भी लिया।

इस संबंध में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री कोठारी ने कहा कि यह आयोग द्वारा किया गया एक सराहनीय कार्य है, चूँकि न केवल राष्ट्रपति भवन परिसर के 50 मालियों के लिए एक एपिकल्चर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया - जिसमें मालियों (गार्डनर्स) को इसके व्यापक विस्तार के बारे से भी अवगत कराया तथा उन्हें मधुमक्खी वाटिका के महत्व और इसके देखरेख करने के तरीके के सम्बन्ध में एवं वनस्पतियों और जीवों के देखरेख करने में मधुमक्खी-पालन के महत्त्व के बारे में जानकारी प्रदान की गई। राष्ट्रपति भवन परिसर में विभिन्न चरणों में कई मधुमक्खी बक्से भी स्थापित किए गए-परिसर में विभिन्न किस्म के पौधारोपण करके वृहद् मात्रा में हरियाली की गई। उन्होंने आगे कहा कि "खादी

(शेष पृष्ठ 5 पर)

एमएसएमई मंत्री द्वारा केआरडीपी योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन

अभिषेक ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा केआरडीपी योजना के तहत स्थापित अमला क्लस्टर के सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन 30 मार्च 2018 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मानव संसाधन राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री एच.एच. शंकराचार्य की उपस्थिति में किया। इस क्लस्टर से करीब 350 लोग जुड़े हैं। वे सभी जाम, अचार, सिरप, लड्डू, बर्फी और कई अन्य जैसे विभिन्न स्वादिष्ट और स्वस्थ उत्पादों का निर्माण करते हैं।

(पृष्ठ 4 से आगे)

और ग्रामोद्योग आयोग के इस पहल से निश्चित रूप से राष्ट्रपति भवन सम्पदा के आसपास और चारों तरफ बागवानी और फूलों की खेती की पैदावार में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि "हम इस शहद और संबंधित उत्पादों को विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए उपहार वस्तुओं के रूप में उपयोग में लायेगें।"

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मधुमक्खीपालन कार्यक्रम, राष्ट्रपति भवन परिसर में 16,000 फूलों के पौधों को अपने दायरे में लेगा जो अबतक अप्रयुक्त रहा है। "चूंकि इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पेड़ हैं, जो परागण के लिए उपयुक्त हैं, यह पड़ोसी क्षेत्रों में फसलों की उपज में बड़े पैमाने पर वृद्धि करेगा। उन्होंने आगे कहा," चूंकि शहद में एंटीऑक्सिडेंट की सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ समृद्ध खनिज और प्रोटीन शामिल होते हैं, इसलिए लोगों को अपने फार्महाउस और बंगलों में भी शहद की खेती को रूचि के रूप में अपनाना चाहिए।" श्री सक्सेना ने आगे कहा, "उन्हें इस बात पर गर्व है कि दिल्ली में प्रधान मंत्री की 'मधुक्रान्ति' भारत के प्रथम नागरिक के निवास स्थान से प्रारंभ हो रही है।"

गौरतलब है कि भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने स्वंय पिछले वर्ष 19 अगस्त को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के हनी मिशन के तहत स्थापित राष्ट्रपति भवन के बगीचे का दौरा किया था।

केवीआईसी के लिए यह सम्मान की बात है कि 9 मार्च 2018 को राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांधी पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पूरे देश की खादी संस्थाओं के 29 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था।

शंभुराजे कारोबारी समूह के साथ एम.ओ.यू.

बोरिपर्डी, दौंड, पुणे में अपने पहले ग्रामीण फ्रेंचाइजी की शुरुआत करने के लिए केवीआईसी को मैसर्स शंभुराजे कारोबारी समूह के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रीता वर्मा की उपस्थिति में आयोग मुख्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

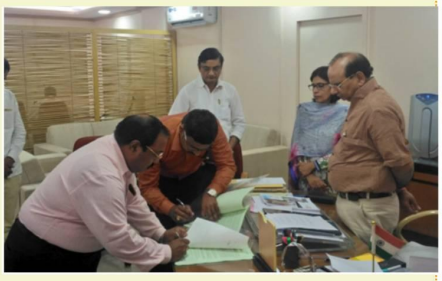

आयोग के पश्चिम क्षेत्र को उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान

आयोग के राज्य कार्यालय, महाराष्ट्र और राज्य कार्यालय, अहमदाबाद को आईएसओ 2001-2015 प्रमाण पत्र मिला।

हस्तकला के साथ एम.ओ.यू.

आयोग द्वारा स्वीकृत एक विशेष शॉप-इन-शॉप के माध्यम से कॉटन बाज़ार परिसरों में खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री करने के लिए आयोग के खुदरा आउटलेट्स 'खादी कॉर्नर' शुरू करने हेतु18 मार्च, 2018 को आयोग मुख्यालय में आयोग ने मैसर्स हस्तकला, ड्रीम बिजनेस वेंचर प्राइवेट लि. के एक प्रभाग के साथ एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये, आयोग के उप मुख्य कार्यकारी आधिकारी श्री के.एस.राव की उपस्थिति में श्री आई. जवाहर, निदेशक, विपणन, खा.ग्रा.आ. और श्री आर. छड्डा, अध्यक्ष, हस्तकला ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

आयोग में महिला दिवस मनाया गया

नई दिल्ली: गुरुवार को राजघाट में स्थित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) में बहुत ही उत्साह के साथ महिला दिवस मनाया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आधुनिक भारत में 'खादी' महिला सशक्तिकरण का आदर्श माध्यम हो सकता है । "खादी और चरखा, जाति, पंथ, लिंग या धर्म पर अंतर किए वगैर प्राचीन काल से सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव का प्रशंसापत्र है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह महिला (गंगाबेन) के अलावा कोई और नहीं थी बल्कि, जिसने पहली बार चरखा महात्मा गांधी को उपहार स्वरूप में दिया था- जिन्होंने इस उपहार का उपयोग ब्रिटिश राज से आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के साधन के रूप में किया था, "उन्होंने आगे कहा," अब समय आ गया है कि खादी के माध्यम से भारत के आर्थिक परिवर्तन में महिलाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आना चाहिए । सामाजिक बुराइयों का विकास और उन्मूलन समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना एक मरीचिका के समान रहेगा। "

मिनल मिश्रा ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के महिला कर्मचारियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन दिया और कहा कि यह गर्व का विषय है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग में महिलाओं द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वित्तीय सलाहकार की पदों की अध्यक्षता की जा रही है। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नारायण भी उपस्थित थे।

इससे पहले, महिलाओं का गुलाब और रूमाल (जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद से प्रभावित परिवारों द्वारा तैयार किया गया) से स्वागत किया।

आयोग में महिला दिवस आयोजित

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने कार्यालय मुख्यालय में आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह आयोजित किया इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्त्ता, राजनीतिज्ञ और फैशन डिज़ाइनर श्रीमती शायना एनसी ने आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रीता वर्मा और वित्तीय सलाहकार, श्रीमती उषा सुरेश की उपस्थिति में, आयोग की महिला कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह पर संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों के सम्मान करने वाले समाज से जुड़ा है तथा महिला व पुरुष

दोनों का सम्मान करने और समान व्यवहार करने का आग्रह किया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रीता वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्भय हो कर स्वयं पर विश्वास करना होगा और बिना किसी

झिझक के आगे आना होगा। बाहर से सहयोग मिलता है किन्तु लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसे आपकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है।

वित्तीय सलाहकार, श्रीमती उषा सुरेश ने भी आत्मविश्वास के साथ ही स्वयं को और दूसरों को भी सशक्त बनाने की बात कही।

इस अवसर पर कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर एक पुस्तक भी जारी की गयी।

यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रधान मंत्री की

रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महिलाओं के कारीगरों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सार्थक कदम उठाए हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 5% अधिक सब्सिडी प्रदान की जा रही है तथा खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 80% से अधिक महिलाएं खादी कार्य से जुड़ी हैं, 30% से अधिक महिला उद्यमियों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने विभिन्न उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 86686 में से 48660 को प्रशिक्षित किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सभ्य समाज के निर्माण में सहयोग करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ने हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विभिन्न योजनाओं की सहायता से सफल हुई महिला उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किये, जो निश्चित रूप से उद्यमियों के उभरते हुए समूह को लाभान्वित और प्रेरित करेंगे।

चेन्नई में

आयोग के राज्य कार्यालय, चेन्नई में महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

आयोग की पूर्व वित्तीय सलाहकार श्रीमती माया सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आयोग के राज्य निदेशक, चेनई श्री लक्ष्मीनारायणन ने अपना विशेष भाषण दिया। कार्यक्रम में राज्य कार्यालय, चेनई में और खादी भवन के महिला कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

(शेष पृष्ठ 23 पर)

अब खादी के कत्तिनों को मिलेगी दोगुनी मजदूरी

शिवदासपुरा विद्यालय में सोलर चरखा एवं करघा कताई और बुनाई प्रशिक्षण प्रारंभ

जयपुर, 18 मार्च 2018: शिवदासपुरा जयपुर में स्थित राजस्थान खादी ग्रामोद्योग विद्यालय में अगले कुछ दिनों में 30 सोलर चरखों और 05 सोलर करघों की एक-एक इकाई स्थापित की जाएगी, जहाँ कताई और बुनाई का प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया जायेगा जिसके फलस्वरूप खादी की कत्तिनों और बुनकरों के पारिश्रमिक में दो गुनी तक बढ़ोत्तरी हो जाएगी। यह घोषणा आज कत्तिनों और बुनकरों के सम्मेलन में स्थानीय कत्तिनों की मांग पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने की।

अध्यक्ष महोदय ने विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया कि विद्यालय में 10 सिलाई मशीनों की खरीद की गयी है उन पर महिलाओं को सिलाई और रेडीमेड गारमेंट्स का प्रशिक्षण दिया जाये। शीघ्र ही विद्यालय प्रांगण में मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण हेतु बी-बॉक्स भी रखे जायेंगे तथा साबुन, अगरबत्ती, तेलघानी, पापड़, मंगोड़ी आदि ग्रामोद्योगों का प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण और बेरोजगार युवक-युवतियां प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत

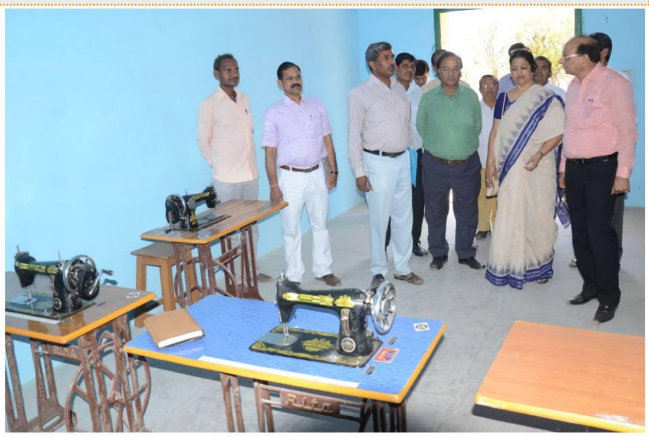

अपना स्व-रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें। इस कार्य के लिए विद्यालय को आयोग से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने विद्यालय को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित करने कि दिशा में कार्य करने का सुझाव दिया।

इस अवसर पर आयोग की दक्ष सदस्य डॉ. शीला राय ने अपने उद्बोधन में महिलाओ का आह्वान किया कि वे घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर अपने परिवार के उत्थान में योगदान दें जिससे उनके बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त

सचिव, एमएसएमई डॉ. अरुण कुमार पांडा के नेतृत्व में एक अधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने 20 से 22 मार्च, 2018 तक सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित इण्डिया सोर्सिंग फेयर -2018 का दौरा किया।

कर आगे बढ़ सकें और यह कार्य केवल खादी और ग्रामोद्योगों के माध्यम से ही हो सकता है।

खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु खादी कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सहयोग करने की दृष्टि से राजस्थान खादी संघ ने पहल की और शिवदासपुरा स्थित राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग विद्यालय पूर्व में सूती खादी, ऊनी खादी, पोलीवस्त्र की कताई, बुनाई एवं होजरी के प्रशिक्षण के साथ साथ विभिन्न ग्रामोद्योगी गतिविधियों यथा – साबुन, अगरबत्ती निर्माण, तेलघानी, सांगानेरी प्रिंटिंग, फल प्रशोधन, मोबाइल रिपेरिंग आदि का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा था. उक्त गतिविधियाँ कतिपय कारणों से शिथिल पड़ गईं थीं। माननीय अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा माननीय दक्ष सदस्या (तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण) डॉ. शीला राय के अथक प्रयासों से विद्यालय में पुनः प्रशिक्षण का प्रारंभ किया गया है।

वर्तमान में विद्यालय में प्रशिक्षण हेतु लगभग 60 कत्तिनें पंजीकृत हैं। 50 नए आठ-ताकुआ चरखों की व्यवस्था की गयी है। इस अवसर पर श्री ए. के. गर्ग, राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री जवाहर सेठिया, अध्यक्ष राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ और अन्य गणमान्य व्यक्ति आयोग और संस्था के अधिकारी और कार्यकर्त्ता आदि उपस्थित थे।

अंत में राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग संस्था संघ के अध्यक्ष श्री रामदास शर्मा, खादी संघ के मंत्री श्री मदनलाल नामा ने आभार व्यक्त किया।

आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रीता वर्मा ने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में विभागीय शब्दावली पर एक पुस्तिका का विमोचन किया।

देहरादून में चरखा वितरण कार्यक्रम

ओ.एन.जी.सी. सामुदायिक केंद्र, कौलगढ़ रोड, देहरादून में तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा सीएसआर योजना के तहत 16 मार्च, 2018 को राज्य कार्यालय, देहरादून द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा चरखे वितरित किए गए और इस कार्यक्रम में "स्वच्छता अभियान" की शपथ ली गयी एवं "स्वास्थ्य किट" भी वितरित किये गए।

कार्यक्रम के दौरान 10 संस्थाओं से आये लगभग 50 कतिनों को नए मॉडल चरखा वितरित किए गए। इससे निश्चित रूप से कतिनों की आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने वित्तीय स्थितियों को बढ़ाने के लिए सुविधाओं को उपयोग में लाने तथा समर्पणभाव के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि बाजार की मांग और खरीदारों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करने का भी प्रयास किया जाए।

इस कार्यक्रम में आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतपाल सिंह, ओ.एन.जी.सी. के कार्यकारी निदेशक श्री आलोक मिश्रा, मुख्य कार्यकारी निदेशक, प्रशासन श्रीमती प्रीता पंत व्यास, और डॉ नितिन चावला और आयोग के कर्मचारी उपस्थित थे।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने सं.मु.का.अ. श्री सत्य पाल के साथ 17.03.2017 को देहरादून में पीएमईजीपी इकाई का दौरा किया।

रैम्प पर खादी

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 9 मार्च 2018 को केरल के एर्नाकुलम में एक खादी फैशन शो का आयोजन किया। इस खादी फैशन शो में 'खादी फॉर नेशन', 'खादी फॉर फैशन' अवधारणा पर महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए उत्कृष्ट और प्रचलित आधुनिक खादी डिजाइन प्रदर्शित किये गए ।

केरल में यह 16 वां खादी फैशन शो आयोजित किया गया और इस वर्ष का यह दूसरा फैशन शो था। 'प्रत्येक फैशन शो' का उद्देश्य-खादी क्षेत्र में उत्पादित तैयार खादी वस्त्र-परिधानों तथा खादी के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना था। इस फैशन शो में प्रदर्शित परिधानों की अनूठी विशेषतायें इनकी बनावट, संरचना एवं उत्कृष्ट और प्रचलित आधुनिक खादी डिजाइन इत्यादि थे। ऐसे शो नई पीढ़ी को आकर्षित करने और खादी की बिक्री के संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हमेशा सहायक होते हैं, और जिससे भावी पीढ़ी के लोगों के लिए खादी को आधुनिक रूप में परिवर्तित किया जा सके। फैशन शो में विशिष्ट भारतीय वस्त्र को लोकप्रिय बनाने के लिए उत्कृष्ट और प्रचलित आधुनिक खादी डिजाइन के परिधान प्रदर्शित किये गए।

इस खादी फैशन शो में हाथ से बुने हुए खादी में केजुअल और फॉर्मल वस्त्र पहने हुए 22 मॉडल मुख्य आकर्षण के केंद्र थे और यह एक स्पष्ट संकेत भी देता है कि समृद्ध भारतीय परंपरा को बनाए रखने में यह फैशनेबल उत्कृष्ट और प्रचलित आधुनिक खादी कैसी हो सकती है।

खादी सूत की मालाः चरखा संग्रहालय के लिए एक अनूठा टिकट

नई दिल्ली: दिल्ली का दिल-कनॉट पैलेस में आप टिकट खरीद सकते हैं जिसे आपको खुशी ही नहीं होगी बल्कि इससे आपको गर्व का भी अहसास हो सकता है।

आप कनॉट प्लेस स्थित पारंपरिक चरखा संग्रहालय में 20 रुपये की एक रंगीन खादी माला खरीद करके यहाँ पर स्थित 100 वर्ष पूर्व सूत से कताई करते हुए चरखे देख सकते हैं और जो आपको आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकता है। हमें एक स्वतंत्र देश और स्वतंत्र सभ्यता के रूप में सुरक्षित रखने के लिए हजारों लोग राष्ट्रपिता के सिद्धातों का अनुपालन करते हैं और इन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए यहाँ चरखा संग्रहालय में एक दर्जन से अधिक विरासत चरखे प्रदर्शित किए गए हैं जहाँ सौ से अधिक वर्षों के इतिहास की झलक दिखायी गई है।

यदि आप प्रसन्नता के इस लिबास को गहराई से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने जो टिकट खरीदा है वह किसी के आजीविका का एक स्रोत है । खादी सूत माला खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय पूनी संयत्र से निकाली गयी अवशेष सामग्री से बनी है । यह गौरतलब है कि यह वह भूमि है जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अर्थात पटना में हाजीपुर स्थित पूनी संयत्र में 30 महिलाएं सूत माला बना रही हैं । देश की राजधानी में भी 10 महिलाएं सूत माला बनाने में लगी हुई हैं। इस सूत माला को 'खादी गुंडी' के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे गंगाबेन कुट्टीर में संग्रहालय के लिए प्रवेश टिकट के रूप में भी जाना जाता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि सूत की माला बनाने के इस कार्य के पीछे कुछ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि "कारीगरों के जीवन में साकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक कारगर प्रयास किया जा रहा है, हमने सीधे ही 45 महिलाओं को रोजगार प्रदान किया अर्थात गंगाबेन कुटीर में 10, हांजीपुर में 30 और सूत माला की रंगाई करने के लिए पांच लोगों को कार्यरत्त करके उन्हें प्रत्यक्ष रूप में रोजगार प्रदान किया है।"

हर बार जब आप यह टिकट खरीदते हैं, तो आपके पास एक स्मृति चिन्ह होता है जो एक कारीगर परिवार को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है। इसके अलावा, यहां तक कि तिहाड़ जेल की महिला कैदियों को भी उनके सुधार कार्यक्रम के तहत आपकी खरीद से फायदा हुआ है। 21 मई 2017 और 31 जनवरी 2018 के मध्य लगभग 20 लाख रूपए से अधिक के टिकटों की बिक्री हुई है। इससे पहले लगभग एक लाख लोगों ने यह टिकट खरीदे हैं।

कुल मिलाकर राजधानी के दिल में एक टिकट - चरखा संग्रहालय के आगंतुकों को संतुष्टि देने के अलावा कुछ लोगों को आजीविका देता है तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग,गरीब खादी कारीगर परिवारों के कल्याण हेतु इन टिकटों की बिक्री से कारीगरों के आजीवका को सुरक्षित रखने के लिए योजना बना रहा है। क्योंकि यह गौरव, सहानुभूति और राष्ट्रीय समर्थन का एक अदृश्य उदाहरण है। यह एक ऐसा टिकट है जो सबसे योग्य लोगों की सीधे आजीविका बनाए रखता है । इससे पहले आप कभी नहीं जानते थे कि आप किसी और की तकदीर के टिकट खरीद सकते हैं।

ऐसे 'कारीगर'-जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है आयोग के 'आपरेशन क्लीन' के तहत उनका सफाया

नई दिल्ली: यह अकारण लग सकता है, लेकिन यह सच है ! खादी कारीगरों के बैंक खातों में सीधे विपणन विकास सहायता (एमडीए) या सब्सिडी के आधार-लिंक्ड भुगतान के कार्यान्वयन के बाद, 'ऐसे 'कारीगर'-जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है- जिनके नाम पर बहुत सी खादी संस्थाओं द्वारा विगत 10 वर्षों से एमडीए दावों का भुगतान किया जा रहा था।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' सिद्धांत के कार्यान्वयन के बाद, वे खादी संस्थाएं, जो कारीगरों की बढ़ी हुई संख्या से केवीआईसी के समक्ष एमडीए का दावा प्रस्तुत करती थीं, उसी सही संख्या में कारीगरों को सब्सिडी प्रदान करना होता था और जब केवीआईसी ने खादी संस्थाओं को भुगतान के लिए आधार का इस्तेमाल अनिवार्य किया, तब खादी संस्थाओं को भुगतान के लिए सही आंकड़ों को उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया, क्योंकि संस्थाओं द्वारा खादी कारीगरों के बारे में दिए गए आंकड़ों के अनुसार उन्हें दिया गया सब्सिडी भुगतान, कारीगरों तक नहीं पहुंच रहा था। एमडीए की गणना, उत्पादन की प्रमुख लागत के 30 प्रतिशत पर की जाती है। इस उपयुक्त राशि में से, खादी-उत्पादक संस्थाओं को 40 प्रतिशत, कारीगरों को 40 प्रतिशत और उन संस्थाओं को शेष 20 प्रतिशत का भुगतान ग्राहकों को छूट देने के लिए किया जाता है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कारण बताया कि "केवीआईसी ने अपनी पद-प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए - मुख्य सतर्कता अधिकारी(सी.वी.ओ.), निदेशकों और सदस्यों को ठीक से कारीगरों की पुष्टि करने के लिए क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया था और लगभग सभी लोगों ने पाया कि कई खादी संस्थाएं, ऐसे 'कारीगर'-जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है-के लिए भी सब्सिडी का दावा करती हैं और इससे उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कारीगरों को दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा उठाया है। "उन्होंने कहा," इस सावधानीपूर्वक उठाये गए कदम से लगभग 7 लाख ऐसे कारीगरों की छंटनी की गई है, जिनका कोई रिकार्ड नहीं है।"

केवीआईसी की भ्रष्टाचार पर शून्य-सहनशीलता नीति है और सभी लेनदेन में पारदर्शिता इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है "इसलिए, हमारे द्वारा महसूस किया गया कि डेटा को शुद्ध करने और गैर-विद्यमान कारीगरों की संख्या को सही करने की आवश्यकता है, ताकि कारीगरों को उनके खातों में एमडीए का सीधे भुगतान किया जा सके। हमने जनवरी 2016 में आधार-वरीयता वाले बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप हम गैर-विद्यमान कारीगरों की संख्या को कम करने में कामयाब रहे, जो सरकारी सब्सिडी को हजम कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे पास यथार्थ और वास्तविक कारीगर हैं और वे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस स्वच्छता अभियान ने कारीगरों और खादी संस्थाओं के वास्तविक आंकड़ों का सृजन किया है; एक ऐसा प्रयास जो पहले नहीं किया गया था। इसलिए, हमारे सफाई अभियान में, कारीगरों की काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या में लाया गया है। "

रोजगार के आंकड़ों के अलावा, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार की गुणवत्ता में आये बदलाव को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।

केवीआईसी के अध्यक्ष ने आगे कहा कि परंपरागत एक-तकुआ चरखा, जिसमें निम्नतम उत्पादन होता है, इसे क्रमशः नए मॉडल 8 और 10 तकुआ चरखा (एनएमसी) में परिवर्तित किया गया है इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है और कारीगरों की आय में भी वृद्धि हुई है। एक तकुआ चरखा की उत्पादन क्षमता प्रति दिन सिर्फ 4 से 5 हैंक है जबकि एनएमसी चरखों की प्रति दिन 20 से 25 हैंक उत्पादन करने की क्षमता है। इससे पहले, खादी संस्थाओं में केवल 2-3 घंटे का काम था क्योंकि मांग उनके लिए कम थी। आज, बेहतर और अधिक आक्रमक विपणन के साथ-साथ केंद्र सरकार से समर्थन द्वारा, सभी क्षेत्रों से ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं और खादी संस्थाओं में कारीगर प्रति दिन 8 से अधिक घंटे काम करते हैं। उन्होंने बताया कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले 2 वर्षों में 18,728 एनएमसी चरखे और 3,582 आधुनिक करघो का वितरण कारीगरों को किया गया। इससे उत्पादन के साथ बिक्री में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, विगत 2 वर्षों के दौरान, 326 नए खादी संस्थानों को जोड़ा गया है, इससे उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि हुई है।

आयोग द्वारा पी.एम.ई.जी.पी. पर जागरुकता शिविर का आयोजन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.आ.) ने बिलावर क्षेत्र के करणवाड़ा और बदधु गांवों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

शिविर के दौरान उप मुख्य मंत्री डॉ. निर्मल सिंह, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सदस्य (उत्तरक्षेत्र) डॉ. हिना शफी भट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहायक निदेशक श्री अनिल कुमार शर्मा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य श्री राजेश बख्शी, बीजेपी की समन्वय समिति के राज्याध्यक्ष ममता सिंह और कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। यह शिविर प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के बारे में सामान्य जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। डॉ. हिना ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और कहा कि भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी हैं।

कुपवाड़ा में उद्यमिता जागरुकता कार्यक्रम

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जम्मू कश्मीर के पम्पोर स्थित पीएमटीसी द्वारा इंडियन आर्मी के सहयोग से 24 मार्च, 2018 को कुपवाड़ा में एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएमईजीपी के साथ-साथ विशेष रूप से मधुमक्खी पालन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई, इस कार्यक्रम में लगभग 80 उम्मीदवारों ने भाग लिया। पीएमटीसी ने मधुमक्खी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों को पंजीकरण प्रपत्र प्रदान किए जो सेना के अधिकारियों के देखरेख में 23.03.2018 को प्रारंभ हुआ।

कार्यक्रम के दौरान सेना के ब्रिगेडियर और अन्य अधिकारियों ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय, जम्मू और कश्मीर एवं पीएमटीसी केंद्र, पम्पोर के कार्यों की प्रशंसा तथा सराहना की।

खादी पंचायत के तहत खादी सम्मेलन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) श्री जी. चंद्रमौली ने 3 मार्च को पेयानूर में खादी पंचायत के अंतर्गत खादी सम्मलेन का उद्घाटन किया। इस लघु खादी सम्मलेन का आयोजन केरल में एक प्रमुख खादी संस्थान पेयानूर फ़िरखा खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में 500 कारीगरों ने भाग लिया।

कारीगरों की सीधे ही शिकायतों की जानकारी लेने के लिए खादी पंचायत का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एक अनूठा प्रयास रहा है। सभी कारीगरों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए काफी दिलचस्पी दिखाई है। इस क्षेत्र में कारीगरों के अनुभवों को जानने के साथ-साथ उनके समक्ष आने वाले समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। कारीगरों ने माननीय सदस्य के समक्ष अपने अनुभवों और शिकायतों को साझा किया है। सदस्य महोदय ने खादी पंचायत में कारीगरों की शिकायतों पर विचार करने का आश्वासन दिया। पैयान्यूर को खादी मक्का के रूप में जाना जाता है और यह वह जगह है जहां नई पैटर्न और डिजाइन के साथ विभिन्न किस्मों के खादी का उत्पादन होता है। रंगों का उपयोग करके वार्प और वेफ्ट (ताना-बाना) पर टाई और डाई विधि से वस्त्र की रंगाई से विशेष चमक आती है। पेयानूर फ़िरखा खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा उत्पादित वस्त्र एक अनोखे संरचना के कारण भारत में और भारत के बाहर लोगों के मध्य बहुत ही प्रचलित है। यह वास्तव में एक अद्भुत भी था और खादी पंचायत में इकट्ठे कारीगरों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे और इस प्रकार उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह बनाई।

केरल में 'इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील' का वितरण

आयोग के राज्य कार्यालय, त्रिवेंद्रम ने खनिज आधारित उद्योग के तहत कारीगरों के लिए वैनाडु विकास सोसाइटी के सहयोग से एक बैठक आयोजित की। आयोग के माननीय सदस्य, दक्षिण क्षेत्र श्री जी. चंद्रमौली ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

खनिज आधारित उद्योग की संवर्धन गतिविधियों के तहत प्रशिक्षित कुम्हारी कारीगरों को 40 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किये गए। 15 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के लिए मान्यता के रूप में प्रशिक्षित कारीगरों को कुम्हारी उद्योग के तहत प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। केरल के वानडु जिले में मानंथवड़ी में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था।

सदस्य(दक्षिण क्षेत्र) द्वारा उर्वू स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्पेटा का दौरा

आयोग के सदस्य, दक्षिण क्षेत्र, श्री जी. चंद्रमौली ने 2 मार्च, 2018 को उर्वू स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्पेटा, वय्नाडू का दौरा किया। संस्थान ने_अपने पहले चरण में स्फूर्ति कार्यक्रम के तहत बेंत और बांस क्लस्टर का कार्यान्वयन किया और वर्ष 2011-12 के दौरान क्लस्टर गतिविधियां राष्ट्र को समर्पित की गई।

प्रतिभाशाली पेशेवरों की एक टीम व्यवस्थित तरीके से संस्थान का नेतृत्व कर रही है। संस्था के पास स्वयं का डिज़ाइन स्टूडियो हैं, जहाँ उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है और जिसमें कलाकारों को बांस पर रचनात्मक डिजाइन बनाते हुए दिखाया जाता है। अब संस्थान बांस मिशन के समर्थन के साथ काम कर रही है और अपने अनूठे फर्नीचर उत्पादों - खिड़की के दरवाजे, फाइल पैड, बैग, बॉक्स के टुकड़े, बांस के आभूषण, अचार इत्यादि जैसे उत्पादों का विशेष रूप से उत्पादन कर रही है। संस्थान के पास एक सामान्य सुविधा केंद्र है जिसमें कच्चे बांस को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए कई मशीन हैं। हालांकि बांस की नैसर्गिक विशेषताओं और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कई उत्पादों को मशीनों से नहीं बल्कि मैन्युअल रूप से उत्पादित किया जा रहा है।

यह क्लस्टर राज्य के सबसे पिछड़े जिले वय्नाडू में स्थित है जहां की मुख्य आबादी जनजातीय है। यह जनजातीय लोग जंगल से बांस का संग्रह करने के साथ-साथ क्लस्टर की विभिन्न उत्पादन गतिविधियों में कार्यों में लगे हैं। संस्थान के सुविधा केंद्र में 20 कारीगर काम कर रहे हैं। कुशल शिल्प कारीगरों को शामिल करके बांस के विभिन्न और अद्वितीय उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। वास्तव में, इन जनजातीय कारीगरों के लिए यह नियमित रूप से अर्जन करने का यह एक चैनल है। हालांकि संस्थान को पर्याप्त कार्यशील पूंजी की समस्या का सामना करना पड़ता है। विचार-विमर्श के दौरान माननीय सदस्य ने संस्थान के पदाधिकारियों को उनके समक्ष आने वाली समस्याओं का हल करने के लिए कुछ सुझाव दिये।

दिनांक 12.03.2018 से 16.03.2018 की अवधि के दौरान आयोग के कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय द्वारा आयोजित एवं राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान(निफ्टम), कुंडली, जिला-सोनीपत, हरियाणा द्वारा संचालित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक दृश्य.

जयपुर में आयोग की विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण डॉ. शीला राय द्वारा खादी कारीगरों को कंबल वितरण।

राज्य कार्यालय, त्रिवेंद्रम ने 2 मार्च, 2018 को खनिज आधारित उद्योग के तहत खनिज आधारित उद्योग की संवर्धन गतिविधियों के तहत प्रशिक्षित कुम्हारी कारीगरों को 40 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किये गए।

एर्नाकुलम में खादी इंडिया प्रदर्शनी 2018

केरल सरकार के जहाजरानी मंत्री श्री कदन्नप्पली रामचंद्रन ने एर्नाकुलम में 1 मार्च 2018 को 'खादी इंडिया प्रदर्शनी-2018' का उद्घाटन किया। आयोग के विभागीय खादी और ग्रामोद्योग भवन, एर्नाकुलम द्वारा 1 मार्च से 15 मार्च 2018 तक इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माननीय सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) श्री जी. चंद्रमौली ने इस प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस उद्घाटन कार्यक्रम में 'कोच्चि की महापौर श्रीमती सौमीनी जैन, विधायक श्री इंडियन हिबी, परामर्शदाता श्री के.वी. कृष्णकुमार और श्रीमती सुधा दिलीप एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग, त्रिवेंद्रम की राज्य निदेशक श्रीमती के.पी. लालिथामणि ने उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदर्शनी में केरल और दूसरे राज्यों से आयी खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं ने भाग लिया।

इस अवसर पर कोचीन के टाउन हॉल में आयोजित खादी इंडिया विशेष प्रदर्शनी में डीएसओ, एर्नाकुलम तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

विभागीय कार्यालय, मेरठ ने कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग के सदस्य, मध्य क्षेत्र श्री प्रकाश तोमर ने की।

स्टील और काष्ठ फर्नीचर के कारीगरों हेतु डिजाइन सेंसिटाईजेशन और गुणवत्ता उन्नयन कार्यशाला

स्फूर्ति कार्यक्रम के तहत स्थापित 'सलेम स्टील और काष्ठ फर्नीचर क्लस्टर' के स्टील और काष्ठ फर्नीचर के कारीगरों के लिए 07 से 09 मार्च 2018 तक एक डिजाइन सेंसिटाईजेशन और गुणवत्ता उन्नयन कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद (भारत सरकार) द्वारा संचालित की गई थी।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्टील और लकड़ी के फर्नीचर के निर्माण में काम कर रहे पहचानित कारीगरों की डिजाइन सेंसिटाईजेशन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जागरूकता प्रदान करना था तथा साथ ही बदलते समय और बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कारीगरों को नए डिजाइन तथा तकनीकी के प्रयोग में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना और प्रशिक्षण प्रदान करना था।

जिला उद्योग केंद्र, सेलम के महाप्रबंधक श्री एस. रामचंद्रन ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, चेन्नई के सहायक निदेशक-।। श्री आर. वसीराजन और एनआईडी, अहमदाबाद के श्री प्रवीण सोलंखी कार्यशाला में उपस्थित थे। स्टील और काष्ठ फर्नीचर विनिर्माण में लगे कुल 30कारीगरों ने कार्यशाला में भाग लिया। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद की टीम ने पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण किया और नए फर्नीचर डिजाइन बनाने के लिए कारीगरों को नए डिजाइन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया।

आयोग के उप निदेशक प्रभारी, शिमला श्री मांगे राम ने केवीआईसी के हनी मिशन कार्यक्रम के तहत रेणुका जी, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश में महिला मधुमक्खीपालकों को बी- बॉक्स वितरण किये। रेणुका जी हिमाचल में जगह का नाम है।

केआरडीपी के तहत प्रशिक्षण

आयोग के एमडीटीसी, बैंगलोर में आर.आई.आई.एस. के कार्यालय प्रबंधन और कर्मचारियों के लिए केआरडीपी के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 48 कार्यालय पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गए।

सीएसआर निधि के सहयोग के माध्यम से चेन्नई में 45 लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए ओएनजीसी ने केवीआईसी के साथ साझेदारी की।

ट्रांसजेंडरों के लिए पी.एम.ई.जी.पी. के तहत विशेष जागरुकता शिविर

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ट्रांसजेंडर समूह के उद्यमी सदस्यों को प्रशिक्षित किया। आयोग के राज्य कार्यालय द्वारा सफल प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को जिला कलेक्टर के हाथों से पी.एम.ई.जी.पी. के स्वीकृत ऋण पत्र वितरित किये गए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि हम इन उद्यमियों की भावना को सलाम करते हैं और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में हमें प्रसन्नता हो रही है।

आयोग के राज्य कार्यालय, चेन्नई ने ट्रांसजेंडर अभ्यार्थियों के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के माध्यम से स्व रोजगार पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था, इसमें 30 लोगों ने भाग लिया, छह लोगों ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है । डीएलटीएफसी ने सभी छह आवेदनों को मंजूरी दी है, इसके पश्चात् इन आवेदनों को बैंकों

के समक्ष प्रस्तुत कर प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी छह स्वीकृत ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी। आयोग द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अधिक से अधिक ट्रांसजेंडरों को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। इस अवसर पर "नारिकुरवार" नमोडिया जनजाति के लोगों के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 12 ऋण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

(पृष्ठ 9 से आगे)

महिला दिवस मनाया.....

खादी दर्शन परिवार

खादी दर्शन परिवार (महिला विंग) के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वत्सल्य ट्रस्ट (अनाथालय घर), कांजूर मार्ग का दौरा किया और खादी दर्शन परिवार की तरफ से खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं का दान किया। एक ... सही पहल।

आयोग के सी.बी. कोरा ग्रामोद्योग संस्थान, बोरीवली में विभिन्न महिला प्रशिक्षकों को आमंत्रित करके महिला दिवस समारोह आयोजित किया गया। उन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया और संस्थान परिसर में वृक्षारोपण उनके हाथों से करवाया गया। ..

बेसिक ब्यूटिशियन पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया, यह पाठ्यक्रम मुंबई के

सीबी कोरा ग्रामोद्योग संस्थान, बोरिवली में

रेडलाइट क्षेत्र कमाठीपुरा में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उस क्षेत्र के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के हाथों से इन प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया।

यह कार्यक्रम , 8 मार्च को सेंट इंटरथनी स्कूल, मुंबई सेंट्रल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित किया गया था।

राज्य कार्यालय, चेन्नई में

राज्य कार्यालय, अहमदाबाद में

केवीआईसी के 'स्वच्छता अभियान' से सरकार के 153 करोड़ रुपये की बचत

नई दिल्ली: यह अकारण लग सकता है, लेकिन यह सच है ! खादी कारीगरों के बैंक खातों में सीधे विपणन विकास सहायता (एमडीए) या सब्सिडी के आधार-लिंक्ड भुगतान के कार्यान्वयन के बाद, ऐसे 'कारीगर'-जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है-जिनके नाम पर बहुत सी खादी संस्थाओं द्वारा विगत 10 वर्षों से एमडीए दावों का भुगतान किया जा रहा था, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अब तक दो साल में अर्थात् वित्त वर्ष 2015-16 से 2017-18 के बीच! सरकारी खजाने के 153 करोड़ रुपये से अधिक बचाए हैं, इतना ही नहीं, केवीआईसी द्वारा अपने रिकॉर्ड को सही करने के साथ-साथ 503 संस्थाओं द्वारा जाहिर तौर पर बताये गए - अवास्तविक कारीगरों के लिए सब्सिडी बंद कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' सिद्धांत के कार्यान्वयन के बाद, वे खादी संस्थाएं जो कारीगरों की बढ़ी हुई संख्या से केवीआईसी के समक्ष एमडीए का दावा प्रस्तुत करती थीं, उसी सही संख्या में कारीगरों को सब्सिडी प्रदान करना होता था और जब केवीआईसी ने खादी संस्थाओं को भुगतान के लिए आधार का इस्तेमाल अनिवार्य किया, तब खादी संस्थाओं को भुगतान के लिए सही आंकड़ों को उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया, क्योंकि संस्थाओं द्वारा खादी कारीगरों के बारे में दिए गए आंकड़ों के अनुसार उन्हें दिया गया सब्सिडी भुगतान, कारीगरों तक नहीं पहुंच रहा था– आयोग का यह प्रयास कुछ आश्चर्यजनक परिणाम लाया है, उसका उदाहरण है : वित्त वर्ष 2015-16 में, एमडीए के करीब 316 करोड़ रुपये का दावा कुल मिलाकर 1,918 खादी संस्थानों को देने के लिए किया गया था। जनवरी 2016 में आधार-वरीयता प्राप्त बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद, वित्त वर्ष 2016-17 में एमडीए की राशि 1,759 संस्थाओं के लिए घटकर 172 करोड़ रूपये हो गई और, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में, केवीआईसी ने 1,413 संस्थाओं के बीच 163 करोड़ रुपये का वितरण किया है।

एमडीए की गणना, उत्पादन की प्रमुख लागत के 30 प्रतिशत पर की जाती है। इस उपयुक्त राशि में से, खादी उत्पादक संस्थाओं को 40 प्रतिशत, कारीगरों को 40 प्रतिशत और उन संस्थानों को शेष 20 प्रतिशत का भुगतान ग्राहकों को छूट देने के लिए किया जाता है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कारण बताया कि "केवीआईसी ने अपनी पद-प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए - मुख्य सतर्कता अधिकारी(सी.वी.ओ.), निदेशकों और सदस्यों को ठीक से कारीगरों की पुष्टि करने के लिए क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया था और लगभग सभी लोगों ने पाया कि कई खादी संस्थाएं, अस्तित्वहीन कारीगरों के लिए भी सब्सिडी का दावा करती हैं और इससे उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कारीगरों को दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा उठाया है। "उन्होंने कहा," इस सावधानीपूर्वक उठाये गए कदम से, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लगभग 7 लाख कारीगरों की छंटनी की गई है।

क्योंकि पंजीकृत कारीगरों की संख्या में 11.6 लाख के बजाय 4.6 लाख पायी गई है, जिससे सरकार पर 152 करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ कम हो गया। इतना ही नहीं, खादी संस्थाओं की संख्या, जोकि सब्सिडी (एमडीए) का दावा करती हैं, वर्तमान वित्त वर्ष में 13 मार्च, 2018 तक 1423 हो गई है, जो वित्त वर्ष में 2016-17 में 1759 और 2015-16 में 1918 थी।

इस प्रकार धन बचाना भी धन अर्जित करने के समान है, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि केवीआईसी की भ्रष्टाचार पर शून्य-सहनशीलता नीति है और सभी लेनदेन में पारदर्शिता इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है "इसलिए, हमारे द्वारा महसूस किया गया कि डेटा को शुद्ध करने और गैर-विद्यमान कारीगरों की संख्या को सही करने की आवश्यकता है, ताकि कारीगरों को उनके खातों में एमडीए का सीधे भुगतान किया जा सके। हमने जनवरी 2016 में आधार-वरीयता वाले बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप हम गैर-विद्यमान कारीगरों की संख्या को कम करने में कामयाब रहे, जो सरकारी सब्सिडी को हजम कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे पास यथार्थ और

(शेष पृष्ठ 29 पर)

संक्षिप्त समाचार

त्रिचूर में कारीगरों को 'मधुमक्खी बॉक्सेस' का संवितरण

त्रिचूर मधुमक्खीपालन क्लस्टर के अंतर्गत पहचानित कारीगरों को 'मधुमक्खी बॉक्सेस' का संवितरण हेतु केरल खादी और ग्रामोद्योग संघ, त्रिचूर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया । आयोग के सदस्य, दक्षिण क्षेत्र श्री जी.चंद्रमौली ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया । इस अवसर पर आयोग की राज्य निदेशक, त्रिवेंद्रम श्रीमती के.पी. लालिथामणि, केरल खादी और ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष श्री सी.एन. बालकृष्णन, केरल खादी और ग्रामोद्योग संघ के सचिव श्री वी. केशवन उपस्थित थे।

नाडिया में ईडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

एसबीआई-आरएसईटीआई, नाडिया, पश्चिम बंगाल में 141 वें ईडीपी बैच का प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् 05.03.2018 को समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां इस बैच में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के 24 लाभार्थियों ने भाग लिया।

बैंकर्स के साथ पी.एम.ई.जी.पी. समीक्षा बैठक

राजस्थान राज्य की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बैठक की एजीएम और डीजीएम आज आयोजित की गई है। यह बैठक जयपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय मुख्य कार्यालय के श्री एम.एल. गुप्ता (डीजीएम) के अध्यक्षता में संपन्न हुई, इस बैठक में वित्त वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्य निष्पादन की समीक्षा की।

माधवरम में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

बेकरी उत्पाद एवं इमिटेशन ज्वेलरी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम श्रीदेवी कला और विज्ञान कॉलेज, पोन्नेरी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सचिव पत्राचार, कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य/ प्रिंसिपल ने अपने विचार व्यक्त किये और भागार्थियों को प्रमाणपत्र संवितरित किए। यह कार्यक्रम सीपीपीआई, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, माधवरम द्वारा आयोजित किया गया एवं बीबीए विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया।

हरियाणा में पी.एम.ई.जी.पी. की एस.एल.एम.सी. बैठक

हरियाणा के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की राज्य स्तरीय मोनिटरिगं समिति की बैठक आज चंडीगढ में उद्योग निदेशक, हरियाणा सरकार, आई.ए.एस. श्री अशोक सांगवान के अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई । इस बैठक में सभी स्टेक होल्डर अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग मंडल, जिला उद्योग केंद्र, एसएलबीसी, बैंकर उपस्थित थे।

चेन्नई में बेकरी उत्पाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

एक 5 दिवसीय बेकरी उत्पाद प्रशिक्षण कार्यक्रम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, तांबाराम, चेन्नई में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में 35 उम्मीदवारों ने भाग लिया । यह कार्यक्रम वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया।

कार्यालय प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोग के एमडीटीसी, बैंगलोर में आर.आई.आई.एस. के कार्यालय प्रबंधन और कर्मचारियों के लिए केआरडीपी के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा बैच आयोजित किया गया। लगभग 60 कार्यालय पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

जयपुर में लोक शिक्षण कार्यक्रम

राज्य कार्यालय, जयपुर ने 26-27 मार्च, 2018 को सेलमपुर खुर्द में एक लोक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। श्री ए. के. गर्ग, राज्य निदेशक, जयपुर ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए आयोग की योजनाओं और कार्यक्रमों पर जानकारी दी।

संक्षिप्त समाचार

केरल में पी.एम.ई.जी.पी. जागरूकता कार्यक्रम

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्रदान कर कताई और बुनाई गतिविधियाँ प्रारंभ करने हेतु केरल स्थित कोडून्गल्लोर में कोडून्गल्लोर म्युनिसिपल कारपोरेशन और जीएसजीएस केन्द्रम, नाथ्यत्तुकुन्नाम के सहयोग से चयनित प्रतिनिधियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों में से 50 लाभार्थियों का चयन किया और उनके आवेदनों को आगामी डीएलटीएफसी के समक्ष रखा जाएगा। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सराहनीय प्रयास रहा है।

चंडीगढ में पी.एम.ई.जी.पी.पर एस.एल.एम.सी. बैठक

पंजाब के पी.एम.ई.जी.पी. कार्यक्रम की राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक चंडीगढ में 12.03.2018 को सचिव, उद्योग व वाणिज्य, पंजाब सरकार के अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में पी.एम.ई.जी.पी. के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई।

कर्नाटक सरकार ने एम.डी.टी.सी. बंगलौर को 2.00 लाख रु. स्वीकृत किए

एम.डी.टी.सी. बंगलौर में बेसिक ब्यूटिशियन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु कर्नाटक सरकार ने 2.00 लाख रु. स्वीकृत किए। इस पाठ्यक्रम में 50 भागार्थियों ने भाग लिया। प्रथम बैच 14 मार्च 2018 से प्रारंभ किया गया।

के.आर.डी.पी. के तहत एफएलईसी बैठक

के.आर.डी.पी. कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु अम्बाला में 19 खादी संस्थाओं के साथ के.आर.डी.पी. की एफएलईसी बैठक अम्बाला में 13 मार्च 2018 को आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोग के आर.आई.डी. के उपनिदेशक प्रभारी श्री के.बी.राव, मेसर्स जी.एस.एल.एक्सपोर्ट प्राइवेट लि. लुधियाना के महाप्रबंधक उपस्थित थे।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दक्षिण क्षेत्र) द्वारा आयोग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दक्षिण क्षेत्र) बंगलौर श्री जी. गुरुप्रसन्ना द्वारा राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, त्रिवेंद्रम का 14.03.2018 को दौरा किया, जहाँ उन्होंने आयोग की विभिन्न योजनाओं जैसे के.आर.डी.पी., स्फूर्ति, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इत्यादि के कार्यान्वयन के प्रगति की समीक्षा की तथा उन्होंने बीमार और समस्याग्रस्त संस्थाओं के इंफ्रस्ट्रकचर को मजबूत बनाने के लिए बैठक की अध्यक्षता की।

बीमार और समस्याग्रस्त संस्थाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में खादी संस्थाओं को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीधी सूची में रखने के लिए दिशानिर्देशों के सरलीकरण के मामले में जिससे आयोग आने वाले वर्षों में खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिक संस्थाओं को शामिल करने हेतु सक्षम करने, कारीगरों को एमएमडीए प्रोत्साहनों का समय पर भुगतान करने और वहां की समस्याओं और फील्ड स्तर पर ई-ऑफिस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण के बारे में चर्चा की गई।

खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में रोजगार में कमी के बारे में खबरों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने एक नए दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ पूर्ण मानव शक्ति का उपयोग करके खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार और बिक्री आदि क्षेत्रों में समकालीन चुनौतियों का सामना किया जा सके।

जेल के कैदियों के लिए रेशा उत्पाद बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोग के राज्य कार्यालय, त्रिवेंद्रम ने 23.02.2018 से 23.03.2018 तक एक माह की अवधि के लिए त्रिवेंद्रम के सेंट्रल जेल के 20 कैदियों के लिए रेशा उत्पाद बनाने हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया। श्रीमती आर. श्रीलेखा, आईपीएस, महानिदेशक, केंद्रीय जेल सुधार, त्रिवेंद्रम ने कार्यक्रम के समापन समारोह का उद्घाटन किया और सेंट्रल जेल में संपन्न कार्यक्रम में फाइबर उत्पाद बनाने में लगे 20 जेल कैदियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गए। आयोग की राज्य निदेशक, त्रिवेंद्रम श्रीमती के. पी. लालिथामणि ने कार्यक्रम में जेल कैदियों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्रदान की। डीआईजी, जेल श्री बी. प्रदीप ने समापन कार्यक्रम समारोह की अध्यक्षता की।

(पृष्ठ 24 से आगे)

वास्तविक कारीगर हैं और वे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस स्वच्छता अभियान ने कारीगरों और खादी संस्थाओं के वास्तविक आंकड़ों का सृजन किया है; एक ऐसा प्रयास जो पहले नहीं किया गया था। इसलिए, हमारे सफाई अभियान में, कारीगरों की काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या में लाया गया है।"

इस बारे में केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केवीआईसी की विभिन्न योजनाओं का पहले से ही डिजिटलीकरण किया गया है और आयोग ने हमेशा अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, "केवीआईसी ने इस साल 1 मार्च को एसएपी प्लेटफॉर्म के तहत एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन के साथ नए डिजिटल युग में प्रवेश किया है। ईआरपी, वास्तविक समय लेनदेन लेखांकन, बजटीय नियंत्रण और समन्वय प्रणाली को सक्षम बनाता है और इसे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ता है।"

(पृष्ठ 3 से आगे)

इस अवसर पर बोलते हुए जीएनएफसी के प्रबंध निदेशक डॉ राजीव कुमार गुप्ता ने कहा, "जीएनएफसी में, हम समाज के विकास में सार्थक योगदान के साथ सतत विकास पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के समर्थन के साथ पीएमईजीपी योजना के तहत इस नीम साबुन इकाई प्रारंभ करने में हमें बहुत प्रसन्नता है, जिसने हमें नीम परियोजना के असाधारण काम को जारी रखने में सक्षम बनाया है, जो हमारे माननीय प्रधान मंत्री के 100% यूरिया नीम कोटिंग के विजन से प्रेरित है।"

उद्घाटन समारोह में, नीम बीज संग्रह का हिस्सा होने वाली महिलाएं मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित की गईं। इस नीम परियोजना का मुख्य केंद्र-महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का उत्थान और महिलाओं एवं उनके परिवार का कल्याण है।

यह परियोजना भारत के छः राज्यों के 53 जिलों के 5000 गांवों में सक्रिय है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 45,000 मीट्रिक टन नीम के बीज एकत्र कर लगभग 4.5 लाख रुपये से अधिक ग्रामीण महिलाओं के लिए 45 करोड़ रुपये से अधिक आय का सृजन हुआ है। यूएनडीपी प्रभाव आंकलन सर्वेक्षण में जीएनएफसी के विजन की सराहना की गई है, जिससे घरेलू हिंसा में कमी आयी है और संपत्ति निर्माण और शिक्षा व्यय में वृद्धि हुई है।

माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात के ग्रामीण लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए विभिन्न मंचों से नीम परियोजना की सराहना की है। इस परियोजना को पोर्टर पुरस्कार, सीएसआर पुरस्कार में सीआईआई-आईटीसी उत्कृष्टता, ग्लोबल सीएसआर अवॉर्ड, गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड, इंडिया सीएसआर अवॉर्ड इत्यादि सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण के काम को आगे बढ़ाने के लिए जीएनएफसी ने सक्रिय रूप से आईएफएफसीओ, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इत्यादि के साथ साझेदारी की है।

अगरतला में क्रेता-विक्रेता बैठक-सह-प्रदर्शनी

बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग पर क्रेता-विक्रेता बैठक-सह-प्रदर्शनी का आयोजन 22-26 मार्च, 2018 को पुरबासा अर्बन हाट, जेल रोड, अगरतला में किया गया।

इसका उद्देश्य आरईजीपी/ पीएमईजीपी/ स्फूर्ति उद्यमियों को उनके उत्पादों का विपणन करने में मदद करना था। असम, बंगाल और त्रिपुरा से करीब 16 इकाइयों ने प्रदर्शनी में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

आयोग के राज्य कार्यालय, अगरतला, त्रिपुरा द्वारा बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग परआयोजित 5 दिवसीय क्रेता-विक्रेता बैठक-सह-प्रदर्शनी के दौरान सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन किया गया।

बहु-उद्योगीय प्रशिक्षण केन्द्र, बैंगलोर में के.आर.डी.पी. के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोग के एमडीटीसी, बैंगलोर में खादी संस्थाओं के कार्यालय प्रबंधन और कर्मचारियों के लिए केआरडीपी के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे बैच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थाओं के लगभग 60 पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

आयोग ने 26 मार्च, 2018 को स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, शिलॉंग में बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग पर क्रेता-विक्रेता बैठक - सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

"पारंपरिक कुम्हारों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण"

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय, कोलकाता द्वारा गंगाजलगती, जिला बंकुरा, पश्चिम बंगाल में 12 से 16 फरवरी, 2018 तक पारंपरिक कुम्हारों के लिए 'खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 कुम्हारों को 'पॉवर पॉटर्स व्हील' वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक कुम्हारों को 'क्ले ब्लंगर मशीन और भट्टी' की स्थापना के बारे में बताया गया।

इस कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों को 'बंकुरा इंजीनियरिंग कॉलेज', 'विश्व भारती' से आये विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

आयोग का कुम्हारी क्लस्टर, बेतुल, म.प्र. और सौर चरखा तथा करघा क्लस्टर, वाराणसी-स्थानीय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्थायित्व पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बड़ोदरा में नया सुसज्जित खादी इंडिया आउटलेट

खादी इंडिया आउटलेट, बड़ोदरा, गुजरात को उत्पादों की विस्तृत और नई श्रृंखला के साथ एक नया सुसज्जित रूप दिया गया है।

हिंदी कार्यशालाएं

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालयों ने निर्धारित दिशा-निर्देशानुसार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों हेतु कार्यालयीन दस्तावेज और दिन-प्रतिदिन कार्यालय के कार्यों को सरल बनाने के लिए हिंदी दिवस और हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की।

19 मार्च 2018 को राज्य कार्यालय, अहमदाबाद ने एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर श्रीमती कीर्ति वोरा, हिंदी अधिकारी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी और उन्होंने, हिंदी में दस्तावेज और दिन-प्रतिदिन के काम के लिए आधिकारिक भाषा के नियमों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यशाला में राज्य कार्यालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया।

आयोग के राज्य कार्यालय, भोपाल ने 20 मार्च, 2018 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ अशोक वी. गणवीर, राज्य निदेशक, भोपाल ने कार्यशाला के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। कार्यशाला में राज्य कार्यालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया।

आयोग के राज्य कार्यालय, जयपुर ने 13 मार्च 2018 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। श्री अरुण कुमार गर्ग, उप निदेशक प्रभारी, राज्य कार्यालय, जयपुर ने कार्यशाला का उद्घाटन किया।

प्रतापगढ़, उ.प्र. में आयोग के राज्य कार्यालय, वाराणसी द्वारा कुम्हारी उद्योग कौशल विकास प्रशिक्षण और कुम्हारी चाक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उद्यमिता विकास संस्थान, ओडिशा द्वारा संबलपुर में पीएमईजीपी लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (ईडीपी) कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

प्रत्युत्तर

'द इकोनॉमिक टाइम्स' में प्रकाशित एक लेख में पूछा गया: व्हाट्स द डील विद खादी?

'द इकोनॉमिक टाइम्स' में प्रकाशित एक लेख में पूछा गया है : Whats the deal with Khadi? 7 लाख नौकरियां तेजी से समाप्त हो गईं, लेकिन उत्पादन में 32% तक वृधि हुई है "। लेख में 2015-16 और 2016-17 के आंकड़े दर्शाए गए है कि कैसे खादी सेक्टर में कार्यरत लोगों की संख्या 2015-16 और 2016-17 के बीच 11.6 लाख से घटकर 4.6 लाख पर पहुंच गई है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है: " करीब से देखने से पता चलता है कि इसमें कुछ रिकॉर्ड हो सकते हैं। लेकिन इन तथ्यों के कारण कितना रोजगार कम हुआ है और आधुनिकीकरण से कितनी नौकरियां चली गई हैं, यह स्पष्ट नहीं है। "

तथापि, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता था, यदि संवाददाता ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) से स्पष्ट किया होता, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं किया गया है।

वास्तविक कहानी इस प्रकार है: -

अतः क्या वास्तव में "रिकॉर्ड्स साफ किये जा रहे हैं" इस पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है।

खादी रोजगार के तथ्य : -

पूर्व में, केवीआईसी द्वारा खादी संस्थाओं को खादी के उत्पादन पर विपणन विकास सहायता (एमडीए) या सब्सिडी प्रदान की जाती थी। उदाहरण के लिए, यदि केवीआईसी द्वारा 100 रुपये खादी संस्थाओं को एमडीए के रूप में भुगतान किया जाता है, तो इसे निम्नलिखित रूप से वितरित किया जायेगा:

खादी संस्थाओं को 40%, खादी कारीगरों को 40 % और शेष 20% संस्थाओं द्वारा उत्पादों पर बिक्री की छूट के लिए भुगतान किया जाता था। पूर्ण धनराशि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी संस्थाओं को प्रदान की जाती थी।

हालांकि, केवीआईसी को इस सम्बन्ध में काफी शिकायतें प्राप्त हुई कि उनके द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी कारीगरों तक नहीं पहुँचती। केवीआईसी ने इस सम्बन्ध में भी शिकायतें प्राप्त की, कि खादी संस्थाओं द्वारा बढ़े हुए कारीगरों पर एमडीए क्लेम किया जाता है। यह भी देखा गया कि वे उन कारीगरों के नाम भी सब्सिडी की मांग करते थे जिन्होंने बुढ़ापे, मृत्यु, बीमारी, विवाह आदि के कारण पिछले 20 वर्षों से यह सेक्टर छोड़ दिया है।

जब यह चित्र सामने आया, केवीआईसी ने आंकड़ों को स्पष्ट करने और उन कारीगरों की संख्या को निकालने सम्बन्धी कार्य शुरू किया जो खादी क्षेत्र से बाहर निकल चुके थे और खादी संस्थाओं से जुड़े नहीं थे।

केवीआईसी ने कारीगरों को एमडीए का सीधे भुगतान करने का निर्णय लिया और आधार-वरीयता प्राप्त बैंक खातों के माध्यम से सीधे ही ऑनलाइन बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली शुरू की । इसे जनवरी 2016 में प्रारंभ किया गया था और इसके परिणामस्वरूप जो कारीगर अस्तित्व में नहीं थे ऐसे कारीगरों के नाम से सब्सिडी क्लेम (गटक जाते थे) की जाती थी, उस संख्या को कम करना शुरू किया।

उपरोक्त प्रयास द्वारा कारीगरों की वास्तविक संख्या उभर कर सामने आयी, इस प्रकार असत्यापित संख्याओं को निकाला गया। इस कार्रवाई के चलते, कारीगरों की काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या के आधार पर नीचे लाया गया है। परिणामस्वरूप, खादी सेक्टर में किसी भी प्रकार रोजगार को कोई नुकसान नहीं हुआ जैसा कि 'इकॉनोमिक टाइम्स' के लेख में दावा किया

प्रत्युत्तर

गया है।

आगे, रिपोर्ट में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) पर भी संदेह जताया गया है। यहाँ पर भी इस तथ्य की जांच और विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है|

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्य-निष्पादन:

पीएमईजीपी के तहत, यह जानना आवश्यक है कि पीएमईजीपी कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन में गिरावट आने के बजाय इसमें वास्तव में बढोतरी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 के दौरान, इस योजना के तहत 3.2 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था, जो 2016-17 में बढ़कर 4.10 लाख हो गयी। वास्तविक संख्या 4.49 लाख है।

चालू वर्ष 2017-18 के दौरान, जनवरी, 2018 तक 64% रोजगार का सृजन किया गया और शेष दो माह में यह आंकड़े 100% से अधिक होने की उम्मीद है।

वास्तव में, हाल ही के कुछ वर्षों में पीएमईजीपी के तहत केवीआईसी के रिकॉर्ड सर्वथा बहुत अच्छे रहे थे। 2016-17 में केवीआईसी के स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन के कुछ निष्कर्ष बताते हैं कि जहां तक खादी और ग्रामोद्योगों से संबंधित है, पीएमईजीपी के तहत रोजगार सृजन में वृद्धि हुई है।

चूंकि केवीआईसी ने पीएमईजीपी के तहत आवंटित सब्सिडी के 100% से अधिक लक्ष्य हासिल किए, लगभग 4 लाख नए रोजगार का सृजन किया, अनुमानित परियोजना लागत 4,800 करोड़ रुपये के साथ, जो वित्त वर्ष 2015-16 के मुकाबले लगभग २४% की भारी वृद्धि को दर्शाती है|

यहां तक कि केवीआईसी की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में पीएमईजीपी के उत्कृष्ट प्रदर्शन, आवंटन और रोजगार सृजन सहित परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से कहा गया है कि 2008-09 में कार्यक्रम शुरू होने के बाद, यह सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है।

खादी में परिवर्तन:

रोजगार के आंकड़ों के अलावा, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार की गुणवत्ता में आये बदलाव को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।

परंपरागत एक-तकुआ चरखा, जिससे बहुत कम उत्पादन होता है, इसे क्रमशः नए मॉडल 8 और10 तकुआ चरखा (एनएमसी) में परिवर्तित किया गया है, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है और कारीगरों की आय में भी वृद्धि हुई है। एक तकुआ चरखा की उत्पादन क्षमता प्रति दिन सिर्फ 4 से 5 हैंक है जबकि एनएमसी चरखों की प्रति दिन 20 से 25 हैंक उत्पादन करने की क्षमता है।

इससे पहले, खादी संस्थाओं में केवल 2-3 घंटे का काम था क्योंकि मांग उनके लिए कम थी। आज, बेहतर और अधिक आक्रमक विपणन के साथ-साथ केंद्र सरकार के समर्थन से, सभी क्षेत्रों से ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। अतः खादी संस्थाओं में कारीगर प्रति दिन 8 से अधिक घंटे काम करते हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले 2 वर्षों में 18,728 एनएमसी चरखे और 3,582 आधुनिक करघों का वितरण कारीगरों को किया गया। इससे उत्पादन के साथ बिक्री में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, विगत २ वर्षों के दौरान, 326 नए खादी संस्थाओं को जोड़ा गया है, इससे उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि हुई है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कहानी वास्तव में नौकरियों की संख्या में गिरावट के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि यह कारीगरों के जीवन को समृद्ध करती है, अर्थात, जो पैसे उन्हें मिलना चाहिए वह प्रत्यक्ष तौर पर उन्हें प्राप्त हो रहा है|

President of India @rashtrap... · 1h

Extraction of honey formally begins at President's Estate Apiary, in partnership with KVIC. The Apiary was opened by #PresidentKovind on August 19, 2017, World Honey Bee Day

narendramodi_in @narendra... · 2h

#Aadhaar helps govt save over Rs. 1.5 billion in subsidy payment to **khadi** artisans business-standard.com/article/econom... via NMApp

Aadhaar helps govt save over Rs 1.5 bn in subsidy payment to khadi artisans

March 21st, 2018

Aadhaar-based payment of subsidies to khadi artisans has reduced the number of "ghost accounts" and saved the government over Rs 1.5 billion, the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has said. With the cleans-

12 57 130

epaper.punjabkesari.in/m5/156697

के.वी.आई.सी. ने ग्रामीणों को दी योजनाओं की जानकारी

हिना ने महिला सशक्तिकरण पर दिया बल

श्रीनगर, 4 मार्च (मजीद): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने जम्मू में बिलावर क्षेत्र के करनवाडा और भड्डू गांवों में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं विशेषकर के.वी.आई.सी. द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा. निर्मल सिंह, के.वी.आई.सी. की उत्तरी क्षेत्र की अध्यक्षा डा. हिना शफी भट्ट, भाजपा संगठन की समन्वय कमेटी की प्रदेश अध्यक्षा ममता सिंह, के.वी.आई.सी. के राज्य सदस्य राजेश कुमार बख्शी, के.वी.आई.सी. के सह निदेशक अनिल कुमार शर्मा आदि मौजूद थे।

डा. हिना ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने पहले से ही कई योजनाओं को शुरू कर दिया है जिनका लाभ उठाने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा स्वयं का काम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। के.वी.आई.सी. भी महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। गांव की हर महिला अपना काम शुरू करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकती है, जिसमें ऋण पर उनको शहरी इलाकों में 25 प्रतिशत, जबकि ग्रामीण इलाकों में 35 प्रतिशत सबसिडी भी दी जाती है।

उन्होंने कहा कि घर में बैठकर ही महिला प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) योजना के तहत विभिन्न इकाइयों को स्थापित कर सकती है, साथ ही इकाइयों को स्थापित करने के लिए उनको विभाग प्रशिक्षित भी करेगा।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है, जिसे गरीबों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्त्ताओं को मिलकर काम करना होगा।

भाजपा संगठन की समन्वय कमेटी की प्रदेश अध्यक्षा ममता सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक अनिल कुमार शर्मा ने पी.एम.ई.जी.पी. के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस योजना के तहत छोटे-छोटे उद्योग लगाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं।

सहायक निदेशक अशोक सिंघवी ने ऊर्जा की बचत संबंधी बताया कि क्षेत्र में बायो गैस संयंत्र लगाने के लिए 4-5 पशु होने चाहिएं, इससे 6-7 व्यक्तियों का भोजन बन जाता है। इससे बनी खाद खेती में काम आती है।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित डा. हिना शफी भट्ट व अन्य। (समीर)

Automatic Metrological Centres activated in 2057 revenue circles in State.Pg8

Bharat Satya

English-Weekly

Postal Reg. No.MCN/303/2017-2019 RNI No.MAHENG/2012/42042

Vol - 5 | Issue - 52 | Mumbai | Editor - Ajay Babli Vajarkar | Friday 9 to 15 March 2018 | Pages-8 | Price -2/-

CMji Pls immediately ban production of liquor in Maharashtra - 100% Suicides be Stopped
Ajay Vajarkar - Bharat Satya

Editorial >>Pg4
Loneliness ! Loneliness !

Minor irrigation grant distributed to over 1 lakh farmers

Mumbai:The government has distributed Rs 255 crore as grants for minor irrigation sets to 1,02,881 farmers in the state.The money has been deposited in their bank accounts. Agriculture MinisterPandurang Fundkar informed the Vidhan Sabha on Monday. He was replying to a written ques-

International women's day celebrated at KVIC

Mumbai : On the occasion of Women's Day the Khadi & Village Industries Commission (KVIC), Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises celebrated the day on 8th march, felicitating women entrepreneurs of the Khadi sector through Social worker, Politician, and Fashion Designer Shaina N.C who was the chief guest for the event. Shaina said that through education and financial independence women can be empowered. She further said that it is about society respecting women's rights and also urged to respect and treat both the genders equally.Ms Preeta Verma CEO of KVIC said women should believe in themselves and come forward without any hesitation and fear to achieve their goals. The support comes from external environment but it needs your inner strength and determination to achieve the goal.Ms Usha Suresh, Financial Advisor also reiterated about realizing inner strength and empowering themselves and others. A hand book titled sexual Harassment of Women at work place was also released on the occasion.It may be noted that meaningful steps to promote women artisans and entrepreneurs under Prime Minister's Employment Generation scheme have been taken by KVIC. Under the scheme women are being provided 5% more subsidies in comparison to their counter parts and more than 80% women in Khadi and Village Industries sector are associated with khadi work with more than 30% women entrepreneurs. KVIC has also trained 48660 women out of 86686 under its various industry-based training programs. KVIC further pledges to provide a favorable environment for women to move forward to help create a cultured society. Few women entrepreneurs who have built a successful business with the help of KVIC would also share their experience on this occasion which will certainly benefit and inspire the budding group of entrepreneurs.

३ मार्च २०१८ ५

जिल्हा

रोजगाराभिमुख शिक्षण व उद्यमशिलता हिच काळाची गरज - राहूल गजभिये

तालुका प्रतिनिधी / १२ मार्च

शेगाव : स्वयंरोजगार व उद्योजकतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या वतीने सतत कार्य सुरू असून रोजगाराभिमुख शिक्षण व उद्यमशिलता ही काळाची गरज असल्याचे मत खादी व ग्रामोद्योग आयोग नागपूर चे संचालक राहुल गजभिये यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतांना व्यक्त केले. व या संदर्भात माऊली अभियांत्रिकी महाविद्यालयात राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांचे कौतूक केले.

स्वयंरोजगार व उद्योगजतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी खादी व ग्रामोद्योग आयोगच्या नागपूर विभागीय कार्यालय व माऊली अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यमाने ८ व ९ मार्च रोजी कार्यशाळेचे आयोजन माऊली अभियांत्रिकी महाविद्यालयात करण्यात आले होते.

या कार्यक्रमाला राहुल गजभिये संचालक अरूण मालखेडे विस्तार अधिकारी एस.एस. शंभरकर सिनिअर एक्झीकेटीव केव्हीआयसी नागपूर उपस्थित होते. संस्थेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वरदादा पाटील कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी होते. तर समिर सोलर सिस्टिम्स लि. नागपूर चे संचालक जयंत वाघमारे, खादीचे प्रचारक जेष्ठ नागरिक प्रल्हाद नेमाडे, प्राचार्य डॉ. सी. एम. जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी समन्वयक डॉ. पी. एम. अर्धापूरकर , डॉ. एम.ए.बेग विभाग व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. ग्रामोद्योग आयोगाचे संचालक राहुल गजभिये यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या कार्यशाळेमध्ये खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग नागपूर यांचे मार्फत निबंध स्पर्धा व वादविवाद स्पर्धा घेण्यात आली. प्रथम सत्रात अरूण मालखेडे यांनी केंद्र शासनाच्या केव्हीआयसी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनाची माहिती दिली. तर एस.एस. शंभरकर , जयंत वाघमारे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. व्दितीय सत्रात स्टेट बँक ऑफ शेगाव शाखेचे व्यवस्थापक राकेश राऊल, गोपाल शिंदे, भांडवल उभारणी व बँकींग व्यवस्थेबाबत मार्गदर्शन केले.तसेच खादी व स्वदेशीचे प्रचारक जेष्ठ नागरिक प्रल्हाद नेमाडे यांनी खादी ही वस्तू नसुन ती एक विचारधारा असल्याबाबत राष्ट्रीय एकात्मतेते खादीचे महत्व विद्यार्थ्यांना संबोधीत करतांना व्यक्त केले.

तिसऱ्या निबंध स्पर्धेत कु.अनुप्रिता इंगळे, राहुल यादव, कु अंकिता देशमुख यांना तर वादविवाद स्पर्धेत साहिल धुराटे,सिध्देश कुलकर्णी, कु. पु मोहरील यांना अनुक्रमे प्रथम व्दितीय व तृतिय पारितोषीक, रोख बक्षीस व प्रमाणपत्र देवून गौरविण्यात आले.

समारोपीय अध्यक्षीय भाषणात ज्ञानेश्वरदादा पाटील यांनी स्वयंरोजगार व उद्योग उभानिस विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

कार्यक्रमाचे संचालन प्रा. निशांत लबडे यांनी तर आभार प्रदर्शन अधिक्षक संदीप काळे यांनी केले.

कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतांना राहूल गजभिये

माऊली अभियांत्रिकीमध्ये दोन दिवशीय कार्यशाळा

युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार संबंधी लोन दे रही है : मेहंदीरत्ता

कैथल(बलिन्द्र नरड़)। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्योंग में चल रहे 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत ऋण लाभार्थियों को केवीआइसी के जिला समन्वयक राजपाल जी एवम संस्थान के निदेशकभूपिंदर मेहंदीरत्ता ने प्रमाण पत्र बांटे।राजपाल ने कहा कि सरकार के द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बड़े स्तर पर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश का युवा अपने बलबूते पर बिजनेस कर जीवन में सफलता हासिल कर सके। दूसरी ओर संस्था के निदेशक भूपेंद्र सिंह मेहंदीरत्ता ने बताया कि छह दिवसीय परीक्षण के दौरान संस्था की तरफ से लोन संबंधी सभी जानकारी लाभार्थियों को दी जाती है ताकि भविष्य में लोन आवेदक को बैंक संबंधी या फिर संस्था संबंधी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।इस अवसर पर संस्थान द्वारा चलाए रही विभिन्न कार्यक्रमो के बारे में बताया गया। यह परीक्षण निशुल्क दिए जाते है।संस्थान द्वारा 55 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते है।बैंको द्वारा 1 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गए है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने कार्यालय मुख्यालय में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता शायना एनसी ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। इस मौके पर आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रीता वर्मा और वित्तीय सलाहकार ऊषा सुरेश उपस्थित थीं। 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न' पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

नारसन में शुक्रवार को खादी आयोग के चेयरमैन का स्वागत करते लोग। ● हिन्दुस्

खादी आयोग के चेयरमै
ने महिलाओं को चरखे बां

नारसन | हमारे संवाददाता

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना का लोगों ने भव्य स्वागत किया।

नारसन बार्डर पर कौशल्या ग्रामोद्योग संस्थान के महासचिव नितिन त्यागी, हार्दिक सेवा संस्थान और उत्तराखंड जनजागृति समिति ने विनय कुमार सक्सेना का स्वागत किया। इस मौके पर

और अधिक बढ़ावा देने के लिए लोगों से आगे आने का आह्वान कि उन्होंने कहा कि खादी हमारे दे पहचान है। इसका लगातार स्को रहा है। इस दौरान 200 महि को न्यू मॉडल चरखा वितरित गया। इस दौरान यशपाल सिंह, त्यागी, नितिन त्यागी, रजनीश राहुल त्यागी, सोमपाल सिंह, राम यादव, कुलदीप भारद्वाज, जाकिर

Hina emphasises on women empowerment

Dy CM, Dr Nirmal Singh along with Chairperson KVIC (NZ), Dr. Hina Shafi Bhat during the programme.

■ STATE TIMES NEWS

BILLAWAR: Khadi and Village Industries Commission (KVIC) orgainsed an awareness camp under the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) here at Karanwara and Bhaddu villages of Billawar.

During the camp, Dy Chief Minister, Dr. Nirmal Singh, KVIC (NZ) Chairperson Dr. Hina Shafi Bhat, KVIC Assistant Director Anil Kumar Sharma, KVIC State member Rajesh Bakhshi and BJP's Coordination Committee State President Mamta Singh were also present.

The programme was organised with an aim to make general public aware about the schemes of Khadi and Village Industries Commission with special focus and benefits under PMEGP scheme.

Speaking on the occasion, Hina emphasised on women empowerment and said that the Central Government has already started many schemes for the empowerment of women. She impressed upon the artisans to take benefits of the schemes of KVIC and establish their unit to create employment for themselves and generate employment to other co workers.

During the programme, Anil Kumar Sharma highlighted the salient features of the PMEGP and other schemes available with KVIC.

Provisional Selection List of the Candidate
Dated 31-05-2017 In Respect of District Ca
PROVISIONAL SELECTION LIST

S.No.	Name	Parentage
1.	Santosha Devi	D/o Gulab Chand

WAITING LIST

S.No.	Name	Parentage
1.	Mehroon Nisa	D/o Javeed Iqbal

DIP/J-11730/18
Dt: 03-03-2018

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता शायना एनसी व अन्य.

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह आयोजित किया गया.जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रवक्ता एवं फैशन डिज़ाइनर शायना एनसी मौजूद थीं.आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रीती वर्मा और वित्तीय सलाहकार उषा सुरेश की उपस्थिति में शायना एनसी ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है.उन्होंने महिला व पुरुष दोनों का सम्मान करने और समान व्यवहार करने का आग्रह किया. इस अवसर पर कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न नामक एक पुस्तक भी विमोचन किया गया.

कौशल्य विकास प्रशिक्षणाला सुरुवात

भद्रावती : खादी व ग्रामोद्योग आयोग मुंबईच्या वतीने कौशल्य विकास योजना अंतर्गत सावेला जि. गडचिरोली येथे पाच दिवसीय कुंभारी कला संबंधी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले. सदर प्रशिक्षणाचा प्रारंभ प्रादेशिक कुंभारी प्रशिक्षण केंद्र ग्रामोदय संघ भद्रावती येथून झाला. खनिज आधारित निदेशालयाच्या उन्नयन कार्यक्रमांतर्गत सदर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला विभागीय कार्यालय नागपूरद्वारा आर्थिक सहाय्य प्राप्त झाले आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सावेला गावाचे सरपंच मोरेश्वर पलू उसेंडी उपस्थित होते. उद्घाटन महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे मुख्य समन्वयक कांता बनकर यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी प्रादेशिक कुंभारी प्रशिक्षण केंद्र ग्रामोदय संघ भद्रावतीचे प्राचार्य जितेंद्र कुमार, गिता गुड्डी, विक्रम निपर्डे, गिता सेनु कडयामी उपस्थित होते. संचालन सुधीर गोटा यांनी केले. प्रशिक्षणाचा उद्देश कारागिरांना उत्कृष्ट कला प्रदान करून त्यांच्या उत्पादनात मुल्यवृद्धी करणे हा असल्याचे मान्यवरांनी सांगितले.

रिम्समध्ये 'उडान २०१८' कार्यक्रम

लोग मौजूद रहे।

boundaries of design and creativ- received a huge response from nity across India and Nepal. Over presence of eminent architects Kulwal, CEO at Birla White.

KVIC's 'SwachchtaAbhiyaan' saves Government's Rs 153 crore

Forever News

New Delhi: It may sound unpalatable, but it is true. After the implementation of Aadhar-seeded payment of Marketing Development Assistance (MDA) or subsidy – directly in the bank account of Khadi artisans, the 'ghost' artisans – on whose names MDA used to be claimed by many Khadi institutions from the last 10-odd years, the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has so far saved over Rs 153 crore of government exchequer in two fiscal years, i.e. between FY 2015-16 to 2017-18! Not only that, with the cleansing of records by KVIC – as many as 503 institutions – apparently running on ghost artisans – stopped claiming subsidy!

After the implementation of 'Digital India' doctrine of Prime Minister Narendra Modi, those Khadi institutions, who were claiming MDA on inflated number of artisans, from the KVIC, had to provide correct number of artisans. And, when KVIC made use of Aadhar mandatory, for the Khadi institutions for providing correct data following serious complaints against many of them that the subsidy, which is given to them for onword payment to Khadi artisans, was not reaching the artisans – it brought some astonishing results. Sample them: In the FY 2015-16, MDA of around Rs 316 crore was claimed and given to altogether 1,918 Khadi institutions. After the implementation of online Direct Benefit Transfer (DBT) system through Aadhar-seeded bank accounts in January 2016, the MDA's amount was reduced to Rs 172 crore for 1,759 institutions in the next fiscal 2016-17. And, in the present fiscal 2017-18, the KVIC has disbursed Rs 163 crore among 1,413 institutions.

MDA is calculated at 30 percent of prime cost of production. Out of this eligible amount, 40 percent is paid to the Khadi-producing institutions, 40 percent to the artisans and remaining 20 percent to those same institutions for giving discounts to customers.

KVIC Chairman Vinai Kumar Saxena categorically explains the reason. "The KVIC ranks and files – right from CVO, directors and members were asked to move in the field to verify the artisans. Almost everyone found that the many Khadi institutions used to claim subsidy even for the non-existing artisans thereby usurping subsidy meant for artisans in the last 10-odd years," he said, adding, "This meticulous exercise has weeded out almost 7 lakh fake artisans as the number of registered number of artisans was found 4.6 lakh instead of inflated 11.6 lakh, thereby reducing the subsidy burden on the government worth Rs 152 crore. Not only that, the number of KIs, who claimed subsidy (MDA) has also come down to 1423 in current FY till 13th March 2018 from 1759 in FY 2016-17 and 1918 in 2015-16." Thus proving the adage money saved is money earned, the Chairman said that the KVIC has zero-tolerance policy on corruption and transparency in all transactions is its top priority. "A need was therefore, felt by us to cleanse the data and remove numbers of the non-existing artisans, so that the MDA could directly be paid to the artisans in their accounts. We introduced online Direct Benefit Transfer (DBT) system through Aadhar-seeded bank accounts in January 2016, which resulted in flushing out 'ghost' artisans who were usurping government subsidy," he said. www.forevernews.in

Disclaimer : Readers are recommended to make appropriate enquiries and seek appropriate advice before sending money, incurring any expenses, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication.

Forever News Publisher, Printer, Owner S. Suchithra has Printed at Dangat Media Pvt. Ltd., Mehra Centre, 5, Marwah Estate, Off Saki Vihar Road, Saki Naka, Mumbai : 400 072 & Published at 301 Crystal Apartments, 1st Marine Cross Line, Marine Lines, Mumbai- 400 002. Tel : 22072714 Editor S. Suchithra Email : info@forevernews.in, RNI No. MAHENG/2012/47728 Chief Editor: S. Suchithra - responsible for selection

ખાદી ગ્રામોદ્યોગનું સુપર સ્ટોર્સ અને કોર્પોરેટ સેક્ટર સાથે ટાઇઅપ

મુંબઇઃ ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ પંચ (કેવીઆઇસી)એ ખાદીનું વેચાણ વધારવા માટે વિવિધ સુપર સ્ટોર્સ અને કોર્પોરેટ સેક્ટર સાથે હાથ મિલાવવાનું નક્કી કર્યું છે. આ યોજના અંતર્ગત કેવીઆઇસીએ ગ્લોબસ બાદ ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગને લક્ષ્યમાં રાખીને અપના બજાર સાથે ટાઇઅપ કર્યું છે. અપના બજારે ચારકોપ અને મુલુન્ડ ખાતે ખાદી કોર્નરની શરૂઆત કરી છે, જે અન્ય શાખામાં વિસ્તારવામાં આવશે. આ અગાઉ કેવીઆઇસીએ નોઇડા અને અમદાવાદ ખાતે આ પ્રકારના ટાઇઅપ કર્યાં છે. સંસ્થા સોપર્સ સ્ટોપ, સ્ટાર બાઝાર, ઇન્ફિનીટી મોલ, પેન્ટાલૂન, બિગ બાઝાર, ડી માર્ટ વગેરે સાથે પણ સહયોગ સાધવાની વિચારણાં કરી રહી છે. કંપની ટોચની કોર્પોરેટ બ્રાન્ડ સાથે પણ વાટાઘાટો કરી રહી છે. અરવિંદ મિલ ડેનિમ બનાવવા માટે કેવીઆઇસી પાસેથી વર્ષે ૧૦ લાખ મીટર ખાદી ખરીદે છે.

ગોદરેજ એપ્લાયન્સિસ સૌથી ગ્રીનેસ્ટ આઇએસઇઇઆર લોંચ કરવાનો દાવો

મુંબઇઃ ગોદરેજ એપ્લાયન્સિસે દેશનું સૌથી વધુ વીજળીની બચત કરતું ૬.૧૫ આઇએસઇઇઆર લોંચ કરવાનો દાવો કર્યો છે, જે

शिवदासपुरा. खादी विद्यालय में महिलाओं को कम्बल वितरित करते अध्यक्ष विनय कुमार

महिला कातिनों को मिली 30 सोलर अंबर चरखों की सौगात

शिवदासपुरा । खादी ग्रामोद्योग विद्यालय में रविवार को खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना के आतिथ्य में महिला सम्मान समारोह मनाया गया। खादी ग्राम उद्योग में अंबर चरखा कातने वाली महिलाओं को कंबल देकर सम्मानित किया गया। सक्सेना ने 30 सोलर अंबर चरखे एवं 5 सोलर से चलने वाली लूम लगाने एवं 10 सिलाई मशीने देने की घोषणा की। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग को पर्यटन विभाग से जोड़ने की बात कही। राज्य निदेशक एके गर्ग, शीला राय खादी ग्रामोद्योग आयोग के उपनिदेशक कुंज बिहारी, उपाध्यक्ष रामदास शर्मा भी मौजूद रहे।

बरडोती में सड़क से गेवल गारब मिटी में नवीन

Khadi soot mala: A unique ticket for Charkha Museum

OUR CORRESPONDENT

In the heart of Delhi, you can buy a ticket that, apart from giving you some pleasure, can give you a chestful of pride.

For a mere Rs 20, you can buy a colourful Khadi mala at the Heritage Charkha Museum in Connaught place and can view charkhas that spun the earth fabric nearly a hundred years ago and helped determine the path of self reliance, which the father of the nation tread along with thousands, to secure us as an independent country and a free civilization. Over a dozen heritage charkhas are exhibited and a glimpse of the history of over a hundred years is showcased at this museum situated at Palika Bazar Park, just opposite Khadi India outlet.

If you take a deep look down this veneer of pleasure, you will realize that the ticket you bought is a building block of someone's well-deserved livelihood. The 'Khadi soot mala' is made of wasted material drawn from Khadi and Village Industries Commission' s (KVIC) Central Silver Plant. It may be noted that in a land from where Mahatma Gandhi kicked off his Satyagraha, i.e., in the silver plant at Hazipur in Patna, as many as 30 women are making these 'soot malas'. Back in the heart of the national Capital, as many as 10 women are engaged in making these 'soot malas', better known as 'Khadi Gundi' as an entry ticket for the Museum at Gangaben Kuttir.

KVIC Chairman, V K Saxena has some socio-economic perspective behind this act of making 'soot malas', he says, "With a simple effort to bring out positive changes in the lives of artisans, we are providing direct employment to altogether 45 women, i.e., 10 in Gangaben Kutir, 30 at Hazipur and five in the dying work for the 'soots malas.'"

Every time you buy this ticket, you have a memento that provides momentous support to an artisanal family. Besides, even the women inmates of Tihar Jail, under its reformation programme, also get benefited from your purchase.

Between May 2017 and January 2018, these ticket sales have fetched over Rs 20 lakhs. Nearly a lakh people have bought these tickets already.

In a nutshell, a ticket at the heart of the Capital – besides giving satisfaction to the visitors of Charkha Museum, also builds some people's lives elsewhere. And KVIC plans to turn the corpus secured from the sale of these tickets into a trust for the welfare of poor Khadi artisanal families, as this is a unique ticket of pride, sympathy and an invisible purpose of national support. There was never a ticket that so directly sustained livelihoods of most deserving people.

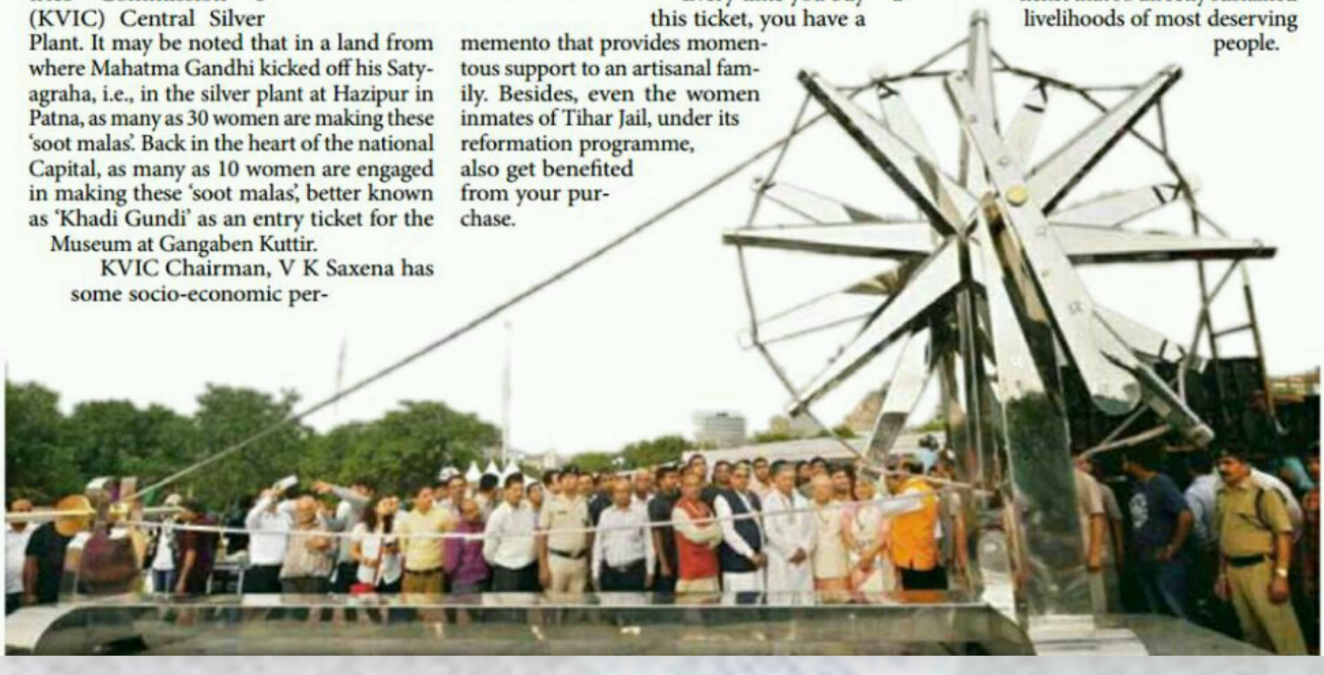

आयोग के चेयरमैन का किया स्वागत

रुड़की (ब्यूरो)। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं सूक्ष्म लघु मंत्रालय भारत सरकार के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना का नारसन में कौशल्या ग्रामोद्योग संस्थान ने महासचिव नितिन त्यागी के नेतृत्व में स्वागत किया। चेयरमैन सक्सेना ने खादी के क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आह्वान किया। बताया कि भारत सरकार खादी के क्षेत्र को और अधिक सशक्त एवं महिला रोजगार को और अधिक बढ़ावा देने के क्षेत्र में सदैव प्रयासरत है। इसी के संबंध में शुक्रवार को ओएनजीसी देहरादून में 200 महिलाओं को न्यू मॉडल चरखा वितरित किया जाएगा एवं पांच संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में 10-10 चरखे के निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग राज्य डायरेक्टर यशपाल सिंह ने खादी को और अधिक बढ़ावा देने के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के विषय में बताया। कार्यक्रम में कौशल्या ग्रामोद्योग संस्थान के संस्थापक सचिव जितेंद्र त्यागी, महासचिव नितिन त्यागी, हार्दिक सेवा संस्थान सचिव रजनीश त्यागी, उत्तराखंड जनजागृति समिति सचिव राहुल त्यागी, सोमपाल सिंह, कुलदीप सिंह, समीर, नइमुद्दीन, जाकिर आदि मौजूद रहे।

ओएनजीसी में खादी संस्थाओं को बांटे चरखे

देहरादून। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय) के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाणित पांच खादी संस्थाओं को स्वाबलम्बी बनाने के लिए सूती कताई करने वाला उन्नत मॉडल का चरखा प्रदान किया।

ओएनजीसी की सीएसआर योजना के तहत कौलागढ़ रोड स्थित ओएनजीसी के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने खादी कताई कार्यकर्ता, संस्थाओं से उच्च कोटी की गुणवत्ता वाले वस्त्रों के उत्पादन के लिए पूरी लगन और निष्ठा से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को स्वाबलम्बी बनाया जा सकता है।

उन्होंने खादी वस्त्रों के नए डिजायन, पैटर्न, रंग व नए फैशन के अनुरुप परिवर्तन कर बाजार की जरूरतों के अनुसार ढालने पर बल दिया। ओएनजीसी के कार्यकारी निदेशक प्रमुख कर्मचारी आलोक मिश्र, कार्यकारी निदेशक प्रधान निगमित प्रशासन प्रीता पंत व्यास ने बताया कि परम्परागत चर्खों के मुकाबले स्पेंडल न्यू मॉडल के चर्खे आठ गुना अधिक उत्पादन में सक्षम है।

उन्होंने कातिनों को स्वच्छता किट भी प्रदान किया।इससे पहले सभी ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यपाल सिंह ने आयोग के अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मौके पर उप निदेशक प्रभारी यशपाल सिंह, सह निदेशक विरेन्द्र उनियाल भी मौजूद थे। संचालन सहायक निदेशक एसआर डोभाल ने किया।

कुम्हारी कला का दिया प्रशिक्षण

संवाद सूत्र, बिनौली: खादी और ग्रामोद्योग आयोग मेरठ के तत्वावधान में बिजवाड़ा गांव में मंगलवार को पांच दिवसीय कौशल एवं उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। जिसमे कुंभकारों को उद्योग लगाने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण का शुभारंभ मुख्य अतिथि सहायक निदेशक ग्रामोद्योग अमृतलाल ने दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि जनपद के ग्रामीण बेरोजगारों को नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण तथा भविष्य में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कुम्हारी उद्योग के अंतर्गत कौशल एवं उन्नयन प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षित युवाओं को आयोग संसाधन एवं अन्य सुविधाएं भी मुहैय्या कराएगा। इस दौरान लखनऊ से आए प्रशिक्षक जयराम प्रजापति ने विद्युत चलित चाक पर मिट्टी से बनने वाले विभिन्न सामान खिलौने, हाथी, घोड़ा, ऊंट, मूर्तियां, फ्लावर पॉट आदि बनाने के लिए सामग्री, तरीका बताया। जिला समन्वयक सुरेंद्रपाल ने बताया कि प्रशिक्षणं के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को विद्युत चलित चाक का वितरण होगा, जिससे वे अपनी क्षमता से अधिक आय प्राप्त करें।

पी.एम. की 'मीठी क्रांति' के लिए के.वी.आई.सी. और सेना ने मिलाया हाथ

सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले में बी-कीपिंग ट्रेनिंग कोर्स शुरू

श्रीनगर, 27 मार्च (मजीद): हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डेयरी उद्योग और शहद की पैदावार (बी-कीपिंग) के जरिए देश में मीठी क्रांति लाने की अपील किए जाने के बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) व भारतीय सेना ने इस मिशन को पूरा करने के लिए एक-दूसरे से हाथ मिलाया है।

प्रधानमंत्री की 'मीठी क्रांति' के हिस्से के रूप में सेना ने ऑप्रेशन सद्भावना के तहत के.वी.आई.सी. के साथ मिल कर सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के युवाओं को लिए बी-कीपिंग ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया। ट्रेनिंग कोर्स की अवधि 7 दिनों की है और द्रगमुल्ला इलाके के बेरोजगार युवाओं ने कैम्प में भाग लिया। इस ट्रेनिंग के लिए द्रगमुल्ला क्षेत्र के ग्रामीणों इलाकों के 100 उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया। ट्रेनिंग के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आजीविका अर्जित करने के लिए मधुमक्खी के बक्से दिए जाएंगे।

कुपवाड़ा में बी-कीपिंग ट्रेनिंग कोर्स के उद्घाटन में सैन्य अधिकारी व डा. हिना भट्ट तथा उपस्थित लोग। (समीर)

ट्रेनिंग कोर्स का उद्घाटन के.वी.आई.सी. की उत्तरी क्षेत्र की अध्यक्ष डा. हिना शफी भट्ट द्वारा किया गया। इस अवसर पर कर्नल विकास वर्मा कार्यवाहक कमांडर थंडर बोल्ट ब्रिगेड, अनिल कुमार शर्मा सहायक निदेशक, लैफ्टिनैंट कर्नल नितेश कुमार, मेजर अनुराग उपाध्याय आदि मौजूद थे।

डा. हिना ने कहा कि सिर्फ आह्वान करने से कुछ नहीं होता, किसी बड़ी क्रांति के मकसद को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कश्मीर में शहद के उत्पादन में बढ़ौतरी हुई है, इसलिए मैं प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं से अपील करती हूं कि वे शहद उत्पादन के लिए अपने खेतों में मधुमक्खी के छत्ते लगाएं, जिससे उन्हें हर साल लाखों रुपए की कमाई हो सकती है।

वहीं कर्नल विकास वर्मा प्रशिक्षुओं को सेना की ओर से पू समर्थन का आश्वासन दिया। उन्हों कहा कि सेना स्थानीय लोगों के कल्या के लिए वचनबद्ध है।

वहीं अनिल कुमार शर्मा सहाय निदेशक/प्रिंसीपल पी.एम.टी.सं के.वी.आई.सी. ने कहा कि मधुमक्ख पालन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर वाले युवाओं को बी-बक्से दि जाएंगे। इससे आजीविका कमाने लिए युवाओं को अब शहरों की अं नहीं जाना पड़ेगा।

અનુસાર રિઝર્વ બેન્કે 26 માર્ચ, 2018ના આદેશ દ્વારા આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કને ₹58.9 કરોડનો દંડ ફટકાર્યો છે. બેન્કે જારી કરાયેલા નિર્દેશોનું પાલન નહીં કરવા બદલ બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, 1949 અંતર્ગત આ દંડ ફટકાર્યો હતો. આવે છે. ભારત તેની જરૂરિયાત પૈકીના અડધોઅડધ ગેસની આયાત કરે છે, જેની કિંમત સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદિત ગેસથી બમણી જેટલી થાય છે. કિંમતમાં કરાયેલા ... પગલે સ્થાનિક ગેસ આધારિત વીજ ઉત્પાદકોના ખર્ચમાં આશરે 3 ટકાનો વધારો થશે.

GNFC- KVIC નીમ સાબુ એકમનો પ્રારંભ

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

રાજ્યકક્ષાના MSME વિભાગના પ્રધાન ગિરીરાજ સિંઘે GNFCના નીમ સાબુ એકમનો ભરૂચ ખાતે પ્રારંભ કર્યો ત્યારે MD ડો. રાજીવકુમાર ગુપ્તા હાજર હતા

પ્રધાન મંત્રીશ્રીના રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ (PMEGP) હેઠળ ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ (KVIC) નો સહયોગ ધરાવતા ગુજરાત નર્મદા વેલી ફર્ટિલાઈઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ (GNFC) ના નીમ સાબુ એકમનો ભરૂચ ખાતે પ્રારંભ થયો છે. આ એકમનું ઉદ્ઘાટન રાજ્યકક્ષાના MSME વિભાગના પ્રધાન ગિરીરાજ સિંઘે કર્યું હતું. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ₹45 કરોડની વધારાની આવક દ્વારા 4.5 લાખ ગ્રામ્ય મહિલાઓનું સશક્તિકરણ કરવામાં યોગદાન આપનાર નીમ પ્રોજેક્ટની આ એક વધુ સીમાચિહ્નરૂપ સિદ્ધિ છે. ગુજરાતના કૃષિ પ્રધાન શ્રી આર.સી ફળદુ પણ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા.

GNFC નો CSR વિભાગ નર્મદાનગર રૂરલ ડેવલપમેન્ટ સોસોયટી (NARDES) દ્વારા સક્રિયપણે આ એકમ માટેની માળખાગત સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવી હતી અને PMEGP અનુસાર મહિલાઓના કૌશલ્યને વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. NARDES દ્વારા KVIC સાથે સંકલન કરીને નીમ સાબુ એકમની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જે ₹4.3 કરોડના વાર્ષિક 225 મેટ્રીક ટન નીમ સાબુનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ મહિલાઓને સક્રિય કરીને તેમને નીમ સાબુ બનાવવાની તાલિમ ભરૂચ આઈટીઆઈમાં આપવામાં આવી હતી. ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં પ્રવચન આપતાં માન. અતિથી વિશેષ ગીરીરાજ સિંઘે જણાવ્યું કે, યુરીયાના 100 ટકા નીમ કોટીંગનું માન. પ્રધાનમંત્રીનું વિઝન સાકાર કરવા બદલ હું GNFCના એમડી ડો. રાજીવકુમાર ગુપ્તાને અભિનંદન પાઠવું છું. આ સાબુ માત્ર ઓર્ગેનિક સાબુ નથી, આ સાબુ ભારતનાં ગામડાની મહિલાઓના પ્રયાસો અને સખત પરિશ્રમથી બન્યો હોવાથી GNFC દ્વારા બનેલા સાબુ ઉપર આપણે દરેક મહિલાનો ચહેરો જોઈ શકીએ છીએ. જ્યારે લીંબોળીઓનુ આ પ્રોડક્ટમાં રૂપાંતર થાય છે ત્યારે મહિલાઓને ગણો નાણાંકિય લાભ થાય છે.

GNFCના મેનેજીંગ ડિરેક્ટર રાજીવકુમાર ગુપ્તા (IAS) એ ... હતું કે "GNFC ખાતે અમે પર્યાવ... વિકાસમાં દ્રઢપણે માનીએ છી... સમાજના વિકાસ માટે ... આપીએ છીએ. PMEG... હેઠળ KVIC સાથે મળીને ... યુનિટના પ્રારંભને કારણે ... નીમ પ્રોજેક્ટની અપવા... કરવાનું શક્ય બન્યું છે.

उद्यमी ने कॉटन और मक्के के यार्न को मिलाकर बनाया फैब्रिक

सूरत के कपड़ा उद्योग से चमकेगा सोलर चरखा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

सूरत. नए-नए प्रयोगों के लिए मशहूर सूरत के कपड़ा उद्योग ने एक और नया प्रयोग किया है। यहां के एक उद्यमी ने सोलर चरखे पर चलने वाले कॉटन यार्न और मक्के के दाने से बने यार्न को मिलाकर फैब्रिक तैयार किया है, जिससे साड़ी, ड्रेस, गारमेंट समेत कई प्रकार के कपड़े तैयार हो सकते हैं। इस फैब्रिक में कई प्रयोग किए जा रहे हैं, जो सफल रहे तो सूरत के कपड़ा उद्योग की मदद से देशभर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने सूरत के लक्ष्मीपति ग्रुप से सोलर चरखे पर चलने वाले कॉटन यार्न पर प्रयोग कर कुछ नया बनाने पर चर्चा की थी। ग्रुप ने

कॉटन यार्न और मक्के के दाने से बने यार्न का वार्पिंग मशीन पर मिश्रण कर नई टैक्नोलॉजी वाली मशीन से कपड़ा बनाया। शुरुआती कठिनाई के बाद इस कपड़े पर कई प्रयोग किए गए, जो सफल रहे। लक्ष्मीपति ग्रुप के एमडी संजय सरावगी ने बताया कि यह काम सरल नहीं था, क्योंकि चरखे की स्पीड कम होने से यार्न टूटते नहीं थे, लेकिन हाइ स्पीड मशीन पर वह टूट रहे थे। पढ़ें सूरत के @ पेज 9

खादी को बढ़ावा देने से बढ़ेंगे रोजगार : विनय

रुड़की। केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना का नारसन में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रमाणित संस्था कौशल्या ग्रामोद्योग संस्थान के महासचिव नितिन त्यागी के नेतृत्व में स्वागत किया गया।

समारोह के दौरान विनय कुमार सक्सेना ने खादी क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया और कहा कि केंद्र सरकार खादी के क्षेत्र को और अधिक सशक्तीकरण एवं इससे महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के डायरेक्टर यशपाल सिंह ने भी इस अवसर पर खादी को और अधिक बढ़ावा देने के क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं के विषय में बताया और उनके प्रचार प्रसार पर बल दिया।

कार्यक्रम में कौशल्या ग्रामोद्योग संस्थान के संस्थापक सचिव जितेंद्र त्यागी, महासचिव नितिन त्यागी, हार्दिक सेवा संस्थान सचिव रजनीश त्यागी, उत्तराखंड जनजागृति समिति के सचिव राहुल त्यागी, गांधी आश्रम देहरादून अध्यक्ष सोमपाल सिंह, सचिव राम सिंह यादव, कुलदीप सिंह, समीर, नईमुद्दीन, गांधी आश्रम हल्द्वानी के प्रतिनिधि विपिन डबराल समेत देहरादून से जाकिर, जसपुर से एवं सभी उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं ने प्रतिभाग किया।

केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन विनय सक्सेना आदि का स्वागत करते खादी संस्थाओं के पदाधिकारी।

ओएनजीसी ने कातने वालों को बांटे आधुनिक चरखे

ग्रामोद्योग आयोग के साथ सहभागिता करें ओएनजीसी: सक्सेना

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की सी.एस.आर. योजना के अन्तर्गत ओ.एन.जी.सी.लि., सामुदायिक केन्द्र में वनय कुमार सक्सेना अध्यक्ष, खादी और गामोद्योग आयोग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय) भारत सरकार ने ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाणित पांच खादी संस्थाओं की 10-10 (कुल 50) कातने वालों को रोजगार प्रदान करने व स्वावलम्बी बनाने हेतु सूती कताई कार्य के लिए प्रत्येक को आठ स्पेण्डल न्यू मॉडल चरखा प्रदान किया गया। आठ स्पेण्डल न्यू मॉडल चरखा द्वारा कताई करने पर कत्तिनों ने परम्परागत चरखे के सापेक्ष उत्पादन लगभग 8 गुना बढ जायेगा तथा धागे

की गुणवत्ता में भी सुधार के साथ-साथ उनकी आय में भी बढोतरी होगी। ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक-प्रमुख कर्मचारी सम्बन्ध आलोक मिश्र एवं प्रीता पन्त व्यास, कार्यकारी निदेशक-प्रधान निगमित प्रशासन द्वारा कत्तिनों को स्वच्छता किट का वितरण किया गया। समारोह के प्रारम्भ में आयोग के अध्यक्ष महोदय एवं ओ.एन.जी.सी.लि. के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों का अवलोकन करने के पश्चात पूज्य बापू महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सत्यपाल सिंह द्वारा आयोग के अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। उप निदेशक-प्रभारी, यशपाल सिंह द्वारा ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक-प्रमुख कर्मचारी सम्बन्ध आलोक मिश्र एवं प्रीता पन्त व्यास, कार्यकारी निदेशक-प्रधान निगमित प्रशासन का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। समारोह में डॉ नितिन चावला, चिकित्साधिकारी, ओ.एन.जी.सी.लि. ने स्वच्छता मिशन पर सारगर्भित व्याख्यान दिया गया। इस अवसर पर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक-प्रमुख कर्मचारी सम्बन्ध आलोक मिश्र ने समारोह को सम्बोधित किया गया एवं आयोग के साथ इस सहभागिता को ओर व्यापक बनाने की आवश्यकता बताई।

इसके अतिरिक्त समारोह में ओ.एन.जी.सी.लि. के वरिष्ठ अधिकारी, खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि, खादी संस्थाओं के फैडरेशन के पदाधिकारी, राज्य कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी प्रतिभाग किया। राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, देहरादून के उप निदेशक- प्रभारी यशपाल सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा सभा का संचालन एसआर डोभाल, सहायक निदेशक ने किया।

खादी कारीगरों का उत्थान प्राथमिकता

मेरठ | वरिष्ठ संवाददाता

खादी के स्तंभ बुनकर कारीगर हैं। मेरठ से हर नई चीज की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति भी मेरठ से ही शुरू हुई थी। खादी की क्रांति भी मेरठ से ही शुरू होगी। मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय से ही देश के 25 फीसदी से अधिक खादी का उत्पादन होता है। खादी की पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। खादी ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य जयप्रकाश तोमर ने यह बात कही।

जयप्रकाश तोमर।

गढ़ रोड स्थित राधा गोविंद मंडप में आयोजित सम्मेलन में पश्चिमी यूपी के विभिन्न जिलों से संस्थाओं के करीब 400 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। सम्मेलन में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से बागपत में प्रस्तावित खादी कारीगर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कार्ययोजना बनाई गई। बैठक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग मेरठ के प्रभारी आरके बुनकर भी मौजूद रहे। इस दौरान संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने समस्याएं बताई और समाधान के लिए आवाज उठाई। मंत्रालय की ओर से खादी के उत्थान के लिए लगातार धनराशि जारी की जा रही है।

केवीआईसी ने खादी संस्थाओं को भुगता... के लिए आधार का इस्तेमाल अनिवार्य कि...

मुंबई, खादी कारीगरों के बैंक खातों में सीधे विपणन विकास सहायता (एमडीए) या सब्सिडी के आधार-लिंकड भुगतान के कार्यान्वयन के बाद, 'अस्तित्वहीन' कारीगरों - जिनके नाम पर बहुत सी खादी संस्थाओं द्वारा विगत 10 वर्षों से एमडीए दावों का भुगतान किया जा रहा था, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अब तक दो साल में अर्थात वित्त वर्ष 2015-16 से 2017-18 के बीच सरकारी खजाने के153 करोड़ रुपये से अधिक बचाए हैं। इतना ही नहीं केवीआईसी द्वारा अपने रिकॉर्ड को सही करने के साथ-साथ 503 संस्थाओं द्वारा ...
गए - अवास्तविक कारीगरों ...
लिए सब्सिडी बंद कर दिया ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिट...
इंडिया' सिद्धांत के कार्यान्वयन ...
बाद, उन खादी संस्थाओं, जो ...
कारीगरों की बढ़ी हुई संख्या ...
केवीआईसी के समक्ष एमडीए व...
दावा प्रस्तुत करती थीं, उसी सह...
संख्या में कारीगरों को सब्सिडी ...
प्रदान करना होता था और जब ...
केवीआईसी ने खादी संस्थाओं ...
को भुगतान के लिए आधार का इस्तेमाल अनिवार्य किया, तब खादी संस्थाओं को भुगतान के लिए सही आंकड़ों को उपलब्ध कराना आवशयक हो गया, क्योंकि संस्थाओं द्वारा खादी कारीगरों के बारे में दिए गए आंकड़ों के अनुसार उन्हें दिया गया सब्सिडी भुगतान, कारीगरों तक नहीं पहुंच रहा था। आयोग का यह प्रयास कुछ आश्चर्यजनक परिणाम लाया है, उसका उदाहरण है। वित्त वर्ष 2015-16 मे...
के करीब 316 करोड़ रुपये का दावा कुल ...
1,918 खादी संस्थानों को देने के लिए किया ...
जनवरी 2016 में आधार-वरीयता प्राप्त बैंक ...
माध्यम से ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (...
प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद, वित्त वर्ष 20...
में एमडीए की राशि 1,759 संस्थाओं के लि...
172 करोड़ रूपये हो गई और, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में, केवीआईसी ने 1,413 संस्थाओं ...

खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन का स्वागत

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं सूक्ष्म लघु मंत्रलय भारत सरकार के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना का नारसन में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार से प्रमाणित संस्थान कौशल्या ग्रामोद्योग संस्थान के पदाधिकारियों ने महासचिव नितिन त्यागी कर नेतृत्व में स्वागत किया। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली से देहरादून जा रहे थे। स्वागत समारोह के दौरान विनय कुमार सक्सेना ने खादी के क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सभी को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए जागरुक किया। विनय कुमार सक्सेना ने इसी के साथ जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार खादी के क्षेत्र को और अधिक सशक्त एवं महिला रोजगार को और अधिक बढ़ावा देने के क्षेत्र में सदैव प्रयासरत एवं इसी के संबंधा में आज ओएनजीसी देहरादून में 200 महिलाओं को न्यू मञ्हल चरखा वितरित किया जाएगा एवं 5 संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूपमें 10-10 चरखे के निशुल्क वितरित किए जाएंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग राज्य डायरेक्टर यशपाल सिंह जी ने इस अवसर पर खादी को और अधिक बढ़ावा देने के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के विषय में बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूपसे कौशल्या ग्रामोद्योग संस्थान के संस्थापक सचिव जितेंद्र त्यागी, महासचिव नितिन त्यागी, हार्दिक सेवा संस्थान सचिव रजनीश त्यागई, उत्तराखंड जनजागृति समिति सचिव राहुल त्यागी, सोमपाल सिंह, गांधी आश्रम देहरादून अध्यक्ष मंत्रि सचिव राम सिंह यादव, कुलदीप सिंह, समीर, नईमुदीन, गांधी आश्रम हल्द्वानी स डबराल, देहरादून से जाकिर, जसपुर से एवं सभी उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं ने स्वागत कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

पांच खादी संस्थाओं को बांटे न्यू मॉडल चरखा

प्रमाणित पांच खादी संस्थाओं की 10-10 कुल 50 कत्तिनों को रोजगार प्रदान करने व स्वावलम्बी बनाने हेतु सूती कताई कार्य के लिए प्रत्येक को आठ स्पेण्डल न्यू मॉडल चरखा प्रदान किया गया

» सक्सेना ने की गैस कॉरपोरेशन की प्रशंसा

» गतिविधियों को निरन्तर चलाने की आवश्यकता

उत्तर भारत लाइव ब्यूरो

uttarabharatlive.com

देहरादून। ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की सीएसआर योजना के अन्तर्गत ओएनजीसी सामुदायिक केन्द्र कौलागढ रोड़ पर खादी और गामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में आयोग से प्रमाणित पांच खादी संस्थाओं की 10-10 कुल 50 कत्तिनों को रोजगार प्रदान करने व स्वावलम्बी बनाने हेतु सूती कताई कार्य के लिए प्रत्येक को आठ स्पेण्डल न्यू मॉडल चरखा प्रदान किया गया। इस दौरान सक्सेना खादी कताई कार्यकर्ताओं एवं संस्थाओं को उच्च कोटी के गुणवत्ता पूर्ण वस्त्रों के उत्पादन हेतु पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया तथा समाज के अन्तिम छोर पर खडे व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाने के आयोग के प्रयास में गैस कॉरपोरेशन की सीएसआर योजना के माध्यम से इस बडी सहभागिता की प्रशंसा की। उन्होंने भविष्य में कॉरपोरेशन एवं आयोग के माध्यम से निर्बल वर्ग को अपनी आजीविका हेतु पूरा समर्थन एवं सहयोग देने की ऐसी गतिविधियों को निरन्तर चलाने की आवश्यकता पर विषेश जोर दिया गया। समारोह के प्रारम्भ में पूज्य बापू महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सत्यपाल सिंह द्वारा अध्यक्ष महोदय का पुश्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेट कर स्वागत किया गया।

उप निदेशक-प्रभारी यशपाल सिंह द्वारा गैस कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक प्रमुख कर्मचारी सम्बन्ध आलोक मिश्र एवं प्रीता पन्त व्यास, कार्यकारी निदेशक-प्रधान निगमित प्रशासन का स्वागत किया गया। सभा का संचालन सहायक निदेशक एस आर डोभाल द्वारा किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय में समारोह संपन्न

मुंबई, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से मुंबई स्थित मुख्यालय में गुरुवार, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और फैशन डिजाइनर श्रीमती शायना एनसी ने आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रीता वर्मा और वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश की उपस्थिति में आयोग की महिलाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों के सम्मान करने वाले समाज से जुड़ा है। उन्होंने महिला व पुरुष दोनों का सम्मान करने और सम्मान व्यवहार करने का आग्रह किया। समारोह में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रीता वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्भय होकर स्वयं पर विश्वास करना होगा और बिना किसी झिझक के आगे आना होगा। बाहर से सहयोग मिलता है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसे आपकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश ने भी आत्मबल को महसूस करने के साथ ही स्वयं को और दूसरों को सशक्त बनाने की बात कही। समारोह में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न नामक एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महिलाओं के कारीगरों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सार्थक कदम उठाए हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 5% अधिक सब्सिडी प्रदान की जा रही है तथा खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 80% से अधिक महिलाएं खादी कार्य से जुड़ी हैं, 30% से अधिक महिला उद्यमियों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने विभिन्न उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 86686 में से 48660 को प्रशिक्षित किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सभ्य समाज के निर्माण में सहयोग करने के महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। समारोह के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विभिन्न योजनाओं की सहायता से सफल हुई महिला उद्यमियों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए, जो निश्चित रूप से उद्यमियों के उभरते हुए समूह को लाभान्वित और प्रेरित करेंगे।

इंस्टाग्राम पर देवी-देवताओं के खिलाफ लोढ़ा का आंदोलन समाप्त

KVIC's 'Swachchta Abhiyaan' saves over ₹153 cr of Govt exchequer in 2 fiscal yrs

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: It may sound unpalatable, but it is true. After the implementation of Aadhaar-seeded payment of Marketing Development Assistance (MDA) or subsidy – directly in the bank account of Khadi artisans, the 'ghost' artisans – on whose names MDA used to be claimed by many Khadi institutions from the last 10-odd years, the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has so far saved over Rs 153 crore of government exchequer in two fiscal years, i.e. between FY 2015-16 to 2017-18! Not only that, with the cleansing of records by KVIC – as many as 503 institutions – apparently running on ghost artisans – stopped claiming subsidy!

After the implementation of 'Digital India' doctrine of Prime Minister Narendra Modi, those Khadi institutions, who were claiming MDA on inflated number of artisans, from the KVIC, had to provide correct number of artisans.

And, when KVIC made use of Aadhar mandatory, for the Khadi institutions for providing correct data following serious complaints against many of them that the subsidy, which is given to them for onword payment to Khadi artisans, was not reaching the artisans – it brought some astonishing results. Sample them: In the FY 2015-16, MDA of around Rs 316 crore was claimed and given to altogether 1,918 Khadi institutions.

SUBSIDY (MDA) PAID BY KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (KVIC) TO KHADI INSTITUTIONS (KIs)

Sl	FY	No. of KIs, claimed subsidy (MDA)	Total MDA claimed and released
1	2015-16	1918	Rs 316 crore
2	2016-17	1759	Rs 171 crore
3	2017-18*	1423	Rs 163 crore

*FIGURES TILL MARCH 13, 2018

After the implementation of online Direct Benefit Transfer (DBT) system through Aadhar-seeded bank accounts in January 2016, the MDA's amount was reduced to Rs 172 crore for 1,759 institutions in the next fiscal 2016-17. And, in the present fiscal 2017-18, the KVIC has disbursed Rs 163 crore among 1,413 institutions.

MDA is calculated at 30 percent of prime cost of production. Out of this eligible amount, 40 percent is paid to the Khadi-producing institutions, 40 percent to the artisans and remaining 20 percent to those same institutions for giving discounts to customers.

KVIC Chairman Vinai Kumar Saxena categorically explains the reason. "The KVIC ranks and files – right from CVO, directors and members were asked to move in the field to verify the artisans.

Almost everyone found that the many Khadi institutions used to claim subsidy even for the non-existing artisans thereby usurping subsidy meant for artisans in the last 10-odd years," he said, adding, "This meticulous exercise has weeded out almost 7 lakh fake artisans as the number of registered number of artisans was found 4.6 lakh instead of inflated 11.6 lakh, thereby reducing the subsidy burden on the government worth Rs 152 crore. Not only that, the number of KIs, who claimed subsidy (MDA) has also come down to 1423 in current FY till 13th March 2018 from 1759 in FY 2016-17 and 1918 in 2015-16."

Thus proving the adage money saved is money earned, the Chairman said that the KVIC has zero-tolerance policy on corruption and transparency in all transactions is its top priority. "A need was therefore, felt by us to cleanse the data and remove numbers of the non-existing artisans, so that the MDA could directly be paid to the artisans in their accounts. We introduced online Direct Benefit Transfer (DBT) system through Aadhar-seeded bank accounts in January 2016, which resulted in flushing out 'ghost' artisans, who were usurping government subsidy," he said, adding, "We have the real and genuine artisans and they are registered with us on online portal. This Swachchata Abhiyaan has led to creation of genuine data of artisans as well as the Khadi institutions; an exercise not attempted earlier. Hence, in our clean-up operation, imaginary number of artisans has been brought to the real numbers."

The Minister of MSME Giriraj Singh said that various schemes of the KVIC have been digitalized in the past and the Commission has always preferred to be transparent in its modus operandi. "KVIC has entered the new digital era on March 1 this year, with the implementation of the Integrated Financial Management System (IFMS) under SAP platform. The ERP enables real-time transaction accounting, budgetary control and reconciliation systems, connecting all its field offices," he said.

Sewapuri Gandhi Ashram
A Beacon of Opportunity

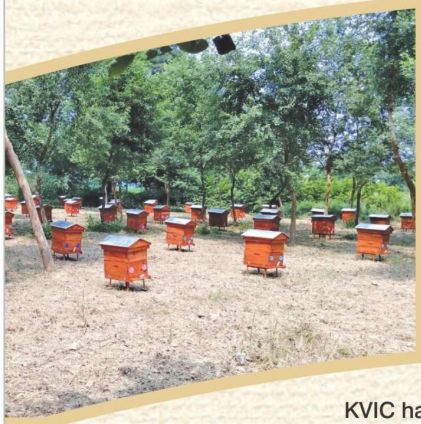

KVIC has become a major catalyst in mobilizing CSR funds of corporate and PSU's in creating much needed sustainable social impact.

Shri Gandhi Ashram in Sewapuri, Varanasi, Uttar Pradesh was founded under the guidance of Mahatma Gandhi in 1946 and offered employment and self-reliance opportunities to the weavers of the village. Besides being an icon of freedom struggle, the Ashram was a source of livelihood and offered valuable training to youth in Khadi weaving so that they could envisage a future.

But, over the past few years the glory of Sewapuri Ashram and its potential stood neglected. A grim silence had descended upon the Ashram.

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) partnered with Rural Electrification Corporation to utilise the latter's CSR funds in renovating and reinstating the ashram to its former glory. A special grant of Rs. 20 Lakh made available by KVIC was also utilised towards this initiative.

Sewapuri Gandhi Ashram Initiatives

250 solar charkhas and 60 solar looms have been provided.

Papad making unit has been established with the assistance of Lijjat Papad with a capacity to produce 250 kg papad per day.

An apiary of 150 Bee Boxes with hives have been set up on the 12-acre campus under KVIC's 'Honey Mission' program.

KVIC's first ever edible salt manufacturing and packaging unit is established on the Ashram, which would be marketed under the brand name of 'Ashram Salt'.

A modern garments unit has been established with an investment of Rs. 60 lakh to provide training in cutting, tailoring and manufacturing readymade garments.

The Sewapuri Ashram Training centre was also revived with a ten-member faculty and imparting knowledge on spinning, weaving, soap and detergent manufacturing, leather and agarbatti making.

The sound of looms, spinning charkhas and humming bees fill the air at Shri Gandhi Ashram Sewapuri now. We endeavor to continue this journey of creating opportunities and fortifying people's hope.

635 direct employment ❖ More than 200 indirect employment

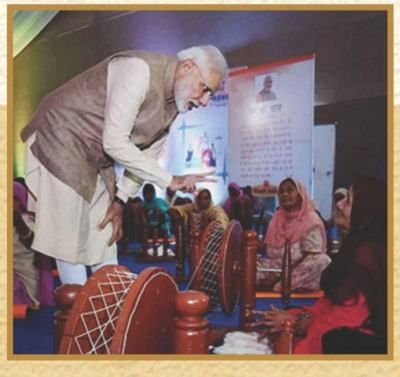

Khadi India

Efforts by KVIC to stir grass-roots change are visible now.

The vision of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi has been instrumental in reviving the ashram. In his 36th address to the nation through his monthly radio programme 'Mann Ki Baat', he recognized the steps taken by KVIC to revitalize the Sewapuri Ashram. His message of Khadi not only being a fabric, but an idea and a principle resonates at the core of all KVIC initiatives.

Other CSR Initiatives by KVIC

Initiatives under Marketing

KVIC has been making persistent efforts for marketing of Khadi products. It has set up modern Khadi lounge, launched franchise scheme, has agreements with Corporate Giants like Raymond of JK Group, Aditya Birla Fashion Retail, Arvind Mills Ltd., for promoting Khadi fabrics and ready-mades. It has also provided gift voucher scheme for corporate gifting to ONGC, obtaining bulk orders from PSUs, government departments and ministries. KVIC has converged with retail chains and malls like Globus, Apna Bazar through "Khadi Korner" counters, opened sales outlets at domestic as well as international airports like Vishakapatnam, Lucknow, Ahmedabad, Varanasi, launched a range of casual wear called vichar vastra specially designed by Ritu Beri. It has also tied-up with premier export institutions like FIEO, CII and FICCI for conducting exhibitions and workshops, and has a tie-up with NIFT for innovative export quality product designs.

Honey Mission and SAHAYOG

KVIC introduced, popularised and appealed masses to adopt modern beekeeping under 'Honey Mission' to develop this industry nationwide. Under this initiative, KVIC has proposed to distribute 1,16,500 bee hives with live bee colonies among 11,650 beneficiaries across the country with a financial outlay of Rs. 55.78 crore and an expected outcome of Rs. 39 crore (in the first year). This will generate for each beneficiary an income of Rs. 40,000 annually which is expected to double in second year.

A campaign called 'SAHAYOG' has been launched inviting donation from corporates/NGOs in which Rs. 42.60 lakh has been collected to support honey mission. Model apiaries with 800 bee hive colonies have been provided at various locations of India under 'SAHAYOG' scheme.

This low-investment and low-input business enterprise has numerous benefits, directly generates economic gains, can be practiced by men, women, and youth and is a crucial avenue towards poverty reduction and enhancing the quality of life.

कामये दुरवतप्राणाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्।

"Gramodaya", 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai 400056, Maharashtra, India.
www.kvic.org.in